नई दिल्ली
24 जून, 2026 बुधवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 84

अनोखे अंदाज़ और निराले टेवर के साथ इन्साफ की डगर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

हरमनप्रीत चार पर, जेमिमा नंबर पांच पर खेलें : मिताली राज 07

संक्षिप्त वार्ता

पोल में घुसी अनियंत्रित उप नगरीय बस, दो बच्चों सहित 8 घायल

इन्दौर। एक सनसनीखेज घटनाक्रम के चलते उस समय अफरातफरी और हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब एक निजी ट्रैवल्स की उप नगरीय बस अनियंत्रित होकर पोल में जा घुसी। जिसमें दो बच्चों सहित करीब आठ लोग घायल हो गए। सभी का एमवाय अस्पताल में उपचार कराया गया। घटना संयोगितागंज थाना क्षेत्र में नवलखा के पास की है। घटना के तुरंत बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया जबकि क्लीनर को लोगों ने पकड़ लिया।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला कि बस के ब्रेक फेल होने के चलते उसे रोकने के लिए ही ड्राइवर ने इसे पोल से टकरा दिया। जिसमें आठ लोग घायल हो गए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वहीं घटना के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया था उसकी तलाश जारी है जबकि क्लीनर को हिरासत में लिया गया है। इंदौर और पीथमपुर के बीच संचालित यह उपनगरीय बस रूबी ट्रैवल्स की है जो अचानक एक पोल में जा घुसी थी बस में कई यात्री सवार थे।

नीट-यूजी री-एग्जाम: मोबाइल से चीटिंग करने वाली छात्रा कोर्ट में पेश

जयपुर। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट)-यूजी 2026 री-एग्जाम में सेंटर के अंदर मोबाइल से चीटिंग करने वाली छात्रा को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने छात्रा को जेल (ज्यूडिशियल कस्टडी) भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद छात्रा चेहरा छुपाते हुए बाहर निकली। वहीं, पुलिस ने मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि मोबाइल का इस्तेमाल केवल जवाब खोजने के लिए हुआ था या प्रश्नपत्र की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास भी हुआ था। यदि जांच में परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल की पुष्टि होती है, तब संबंधित छात्रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

अन्ना हजारे आरटीआई नियमों के खिलाफ करेंगे अनशन

मुंबई। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के नए आरटीआई नियमों का विरोध करते हुए 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यदि 12

जून को लागू किए गए संशोधित नियमों को तत्काल वापस नहीं लिया गया, तो वे अपने गांव रालेगण सिद्धि में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने नए नियमों पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र आरटीआई नियम, 2026 सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना को कमजोर करते हैं। उनका आरोप है कि इन प्रावधानों से नागरिकों के लिए सरकारी सूचनाएं प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा।

पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुईं देश की 65 हस्तियां

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को पद्म पुरस्कार-2026 प्रदान किए गए. देश की कुस 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पुरस्कार पाने वाले में 65 लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, सिंगर अल्का याग्निक और अभिनेता ममूटी शामिल हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए. समारोह में वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह सहित विभिन्न अतिथि शामिल हुए. कुल 65 पद्म पुरस्कारों में दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं.

संविधान लेकर चलने वालों के नक्सली हिंसा के चरम पर हाथ कांपते थे: पीएम मोदी

परोक्ष रुप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में दशकों से जारी नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर परोक्ष हमला बोलकर कहा कि जो लोग आज संविधान दिखा रहे हैं, नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जोर दिया कि दशकों तक ऐसा लगा कि हिंसा का यह दुर्भाग्य इस तरह बना रहेगा, लेकिन उनकी सरकार ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आगे बढ़ाया।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने नक्सल प्रभावित इलाकों को सिर्फ पिछड़ा क्षेत्र करार देकर छोड़ दिया था, जबकि एनडीए सरकार ने उन क्षेत्रों को बदलने की चुनौती स्वीकार की। मोदी सरकार ने वहां के निवासियों को निराशा से बाहर कर प्रगति की उम्मीदें जगा दी। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिन्हें हाल के लोकसभा चुनावों के बाद सांसद के तौर पर शपथ लेते समय और अन्य मौकों पर संविधान की प्रति हाथ में लहराते हुए देखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के मूल मंत्र नेशन फर्स्ट पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बीते 12 सालों में केंद्र सरकार के हर फैसले और हर प्रयास के केंद्र में यही भावना रही है। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे कदम इसी नेशन फर्स्ट सोच का हिस्सा हैं। उन्होंने हाल ही में जी-7 शिखर सम्मेलन के अनुभव को साझा कर कहा कि दुनिया के नेताओं ने महसूस किया कि आज का भारत नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है।

पीएम मोदी ने मध्यम वर्ग को मिली आर्थिक राहतों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2013-14 में 2 लाख रुपए से अधिक की आय पर टैक्स दिया जाता था, जबकि अब 12 लाख रुपए सालाना तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। जीएसटी सुधारों ने टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिससे लोग घर बैठे आयकर रिटर्न भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर लोगों के करीब 40 हजार करोड़ रुपए बचाए गए हैं।

इतना ही नहीं विकास के मोर्चे पर, प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो, ट्रेन और एयरपोर्ट के तेजी से विस्तार पर बात रखी। उन्होंने बताया कि 2014 में रोजाना करीब 28 लाख लोग मेट्रो से सफर करते थे, जो अब बढ़कर 1.28 करोड़ हो गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ रही हैं, और पिछले कुछ वर्षों में देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। साथ ही, केंद्र सरकार ने 100 से अधिक जिलों और 500 से अधिक ब्लॉकों को, जिन्हें पहले पिछड़े क्षेत्र मानकर छोड़ दिया गया था, उन्हें आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक का नाम देकर विकास की मुख्यधारा में लाने का महत्वपूर्ण काम किया है।

2600 साल पहले 1120 बीमारियों का रिकॉर्ड रखने वाले भारतीय ऋषि को स्कॉटलैंड में सम्मान

नई दिल्ली। करीब 2500 साल पहले काशी में एक व्यक्ति की कटी हुई नाक को कुशलता से जोड़कर चिकित्सा जगत को

आश्चर्यचकित करने वाले महर्षि सुश्रुत को आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। भारत ही नहीं, दुनियाभर में उन्हें सर्जरी के पितामह के रूप में सम्मान मिला है। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग के प्लेफेयर ऑडिटोरियम में महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांसे की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें यह सम्मान दिया है। भारत के इन महान ऋषि को दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है। महर्षि सुश्रुत की दूरदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2600 साल पहले ही 300 से अधिक प्रकार की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की थीं।

अब प्लास्टिक कचरे से बना पेट्रोल मिलेगा 32 रुपए लीटर

नई दिल्ली। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर देश के खजाने पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम करने और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से, वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बाद अब देश में एक नए तरीके का पेट्रोल-डीजल तैयार किया गया है, जो न सिर्फ बेहद सस्ता होगा, बल्कि सामान्य तेल जितना ही अच्छा एवरेज भी देगा। मात्र 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर 62 किमी प्रति लीटर का एवरेज मिल जाएगा। वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक मिश्रित प्लास्टिक कचरे को पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन में बदल दिया है। यह नवाचार एक तरफ जहां ईंधन का एक नया और सस्ता विकल्प प्रदान करेगा, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या का भी समाधान करेगा।

परीक्षण सफल, इंजन बदलने की जरुरत नहीं

यह फॉर्मूला केवल फाइलों या लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से परख लिया गया है। भारत के एक प्रमुख दोपहिया निमार्ता कंपनी की तीन मोटरसाइकिलों को इस पेस्ट्रो पेट्रोल से दौड़ाया गया और खास बात यह है कि इसके लिए इंजन में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं हुई। इस प्लास्टिक वाले पेट्रोल से माइलेज भी लगभग सामान्य पेट्रोल जितना ही मिला; 100 सीसी की एक बाइक जिसने सामान्य पेट्रोल से 62 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दिया, वह प्लास्टिक से तैयार एक लीटर पेट्रोल से 60 किलोमीटर दौड़ी। एक और अच्छी खबर यह है कि इस पेट्रोल से होने वाला प्रदूषण भी निर्धारित मानकों के भीतर ही रहा, और इन मोटरसाइकिलों ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया।

100 किलो प्लास्टिक कचरे से बनेगा 50 किग्रा इंधन

रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 100 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस करके लगभग 50 किलोग्राम ईंधन निकाला जा सकता है। कच्चा तेल जहां 24 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर उत्पादित किया जा सकता है, वहीं अपग्रेड करने के बाद इसकी कीमत लगभग 32 रुपये प्रति लीटर होगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तकनीक से उत्पादित तेल 90 फीसदी तक सामान्य पेट्रोल-डीजल जैसा ही है। इस पेस्ट्रो पेट्रोल में कितनी संभावनाएं हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एविएशन कंपनी एयरबस भी जीएसवी के साथ मिलकर काम कर रही है। कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक कचरे से विमान उड़ाने वाले ईंधन (जेट फ्यूल) को भी विकसित किया जा सके।

कतर में दर्दनाक हादसा

विदेश मंत्री ने जताया गहरा दुख

वेब वार्ता, नई दिल्ली

कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए एक दुखद हादसे में कम से कम 12 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जिससे भारत में शोक की लहर दौड़ गई है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुष्टि की है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस हृदय विदारक घटना पर

गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह घटना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक में हुई, जिसने वैश्विक स्तर पर भी चिंता पैदा की है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में कई भारतीय नागरिकों की मौत और घायल होने की खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा है। उन्होंने पुष्टि की कि भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मंत्री ने अपनी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ होने की बात कही, जिससे संकट की इस घड़ी में सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता जाहिर होती है।

दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने भी एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की। दूतावास ने बताया कि रविवार रात हुए रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। दूतावास ने इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। यह बयान भारत सरकार की ओर से अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति गंभीर चिंता को दशार्ता है, विशेषकर विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि हादसे में घायल हुए सभी भारतीय नागरिक फिलहाल स्थिर हालत में हैं और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

अयोध्या: चढ़ावे में आए पैसे गिनने वालों के कपड़ों में नहीं होगी जेब

राम मंदिर चढ़ावे की जांच के बाद सख्त हुए नियम

वेब वार्ता, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच का असर अब मंदिर की व्यवस्थाओं पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

इस जांच के बीच, बैंक प्रबंधन ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया और सख्त ड्रेस कोड लागू कर दिया है, जिसके तहत अब गणना कर्मियों की वर्दी में कोई जेब नहीं होगी। यह कदम चढ़ावा प्रकरण की एसआईटी जांच के बीच अनुबंध के कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जांच के दायरे में आए कुछ कर्मचारियों को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है।

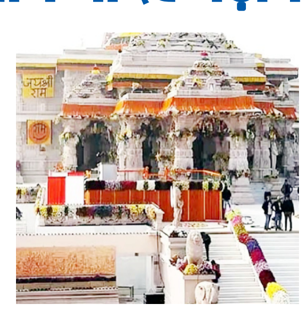

राममंदिर भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर बैंक प्रबंधन को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि जब बैंक के साथ अनुबंध में स्पष्ट नियम बनाए गए थे, तो गणना कर्मियों ने उनकी अनदेखी क्यों की। बताया जाता है कि बैंक ने बनारस की एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को कर्मचारी उपलब्ध कराए थे और उनकी सैलरी भी उसी कंपनी के जरिए दिलवाई गई थी। सूत्रों की मानें तो लगभग 90 फीसदी नियुक्तियां ट्रस्ट पदाधिकारियों के प्रभाव का इस्तेमाल करके करवाई गई थीं और समय-समय पर नियमों में ढील भी इन्हीं पदाधिकारियों की शह पर मिलती रही। हालांकि, बैंक के बड़े अफसरों का कहना है कि अनुबंध दोतरफा हुआ था और बैंक ने अपनी ओर से कर्मचारी नहीं थोपे थे। कायदे से इस संवेदनशील कार्य में बैंक के नियमित कर्मचारी ही होने चाहिए थे।

कर्मचारियों में आशंकाएं

पहले जो कर्मचारी कभी-कभार फोन उठा लेते थे, उन्होंने अब फोन उठाना पूरी तरह बंद कर दिया है। मीडिया से बात करने पर उन्हें खुद के एसआईटी की पूछताछ के दायरे में आने की आशंका लग रही है। दूसरी तरफ, जांच को लेकर कर्मचारियों को विभिन्न आशंकाएं सता रही हैं कि अगर वे पूछताछ के दायरे में आते हैं, तो वे किस तरह से अपना पक्ष रखें, क्योंकि इस मामले में लगातार नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं और पूर्व में कई ऐसी चीजें रही हैं जो इन कर्मचारियों की आंखों के सामने से गुजरी हैं।

फोन लेकर कर्मचारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

अब राम मंदिर से महत्वपूर्ण जानकारियां मीडिया में लीक होने के बाद मंदिर प्रशासन इसको लेकर अत्यधिक सख्त दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों को अब मंदिर के बारे में कोई भी जानकारी देने से मना किया गया है और मोबाइल फोन लेकर कर्मचारियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, कर्मचारियों के परिजनों को भी किसी से कोई बातचीत न करने की हिदायत दी गई है, जिसे एसआईटी के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से राम मंदिर से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां मीडिया को मिल रही थीं, जिसका स्रोत मंदिर प्रशासन पता नहीं कर पा रहा था। सूत्रों के मुताबिक, अब इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और कर्मचारियों को मीडिया से बातचीत करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस कारण से राम मंदिर के बारे में कुछ भी बोलने से कर्मचारी बच रहे हैं।

राज्यसभा सदस्यता समाप्त होने पर कुरियन ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में पुष्टि की गई कि प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, जिसके साथ ही वह अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं रहे। इस अचानक हुए इस्तीफे ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन इसका मुख्य कारण एक संवैधानिक बाध्यता रही है। दरअसल, जॉर्ज कुरियन को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री पद पर बने रहने के लिए संसद के किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य होना अनिवार्य है। कुरियन की राज्यसभा सदस्यता की अवधि हाल ही में पूरी हो गई थी, और उन्हें इस बार दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया।

सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा 'ड्रैकुला तोता'

वेब वार्ता, लंदन

सोशल मीडिया पर आजकल एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे ह्यड्रैकुला तोताह्न कहा जाता है। इस तोते का चेहरा और रंग-रुप पहली नजर में किसी रहस्यमयी या डरावनी फिल्म के पात्र जैसा लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। अपने अनोखे स्वरूप के कारण चर्चा में रहने वाला यह पक्षी प्रकृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक जगत में इस पक्षी को ह्यपेस्केट्स पैरटह्न के नाम से जाना जाता है। इसके शरीर पर मुख्य रूप से काले और धूसर रंग के पंख होते हैं, जबकि पेट और शरीर के कुछ हिस्सों में चमकीला लाल रंग दिखाई देता है। इसकी सबसे खास पहचान इसका सिर है, जिस पर लगभग पंख नहीं होते। यही वजह है कि इसे देखने पर कई लोगों को गिद्ध की याद आ जाती है। इसके काले-लाल रंग और रहस्यमयी चेहरे ने ही इसे ह्यड्रैकुला तोताह्न जैसा लोकप्रिय नाम दिलाया है। हालांकि नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यह कोई खतरनाक या रक्तपान करने वाला पक्षी होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से फलाहारी पक्षी है और किसी भी प्रकार का शिकार नहीं करता।

विशेषज्ञों के अनुसार इसके सिर पर पंख न होना प्रकृति की एक विशेष अनुकूलन प्रक्रिया का परिणाम है। यह पक्षी मुख्य रूप से अंजीर और अन्य रसीले फलों का सेवन करता है। फलों का रस खाते समय चिपचिपा पदार्थ पंखों में न फंसे और सिर साफ बना रहे, इसलिए इसके सिर पर

पंख विकसित नहीं हुए। यही कारण है कि इसका चेहरा अन्य तोतों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ड्रैकुला तोता दुनिया के सबसे बड़े तोतों में गिना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। हालांकि आकार में बड़ा होने के बावजूद इसे देख पाना आसान नहीं है। यह मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी के घने और ऊंचे वर्षावनों में निवास करता है। स्वभाव से यह बेहद शमीर्ला माना जाता है और आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाए रखता है। इसी वजह से इसके बारे में जानकारी सीमित है और इसे जंगलों में देख पाना भी दुर्लभ माना जाता है।

...और पेड़ों के उगने में मदद मिलती है

इसके अलावा इसके आकर्षक लाल पंखों के लिए अवैध शिकार भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। इन खतरों को देखते हुए इसे संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजातियों में शामिल किया गया है और पर्यावरणविद इसके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पक्षी केवल अपनी अनोखी बनावट के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में भी इसकी अहम भूमिका है। फल खाने के बाद यह विभिन्न स्थानों पर बीज फैलाता है, जिससे नए पौधों और पेड़ों के उगने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह जंगलों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में योगदान देता है। मालूम हो कि दुनिया में कई ऐसे पक्षी और जीव-जंतु पाए जाते हैं, जो अपने अनोखे रूप-रंग और व्यवहार के कारण लोगों को हैरान कर देते हैं।

संपादकीय

जंगल के आर्थिक कारनामे

जंगल की विशालता में हिमाचल की आर्थिक क्षमता का एक सर्वेक्षण सामने आया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक सर्वे से यह अनुमान लगाया गया है कि जंगल से कितनी आर्थिक खुशहाली हासिल की जा सकती है। मोटे तौर पर 22600 करोड़ के खजाने का आकलन हुआ है। जंगल का पहली बार मूल्यांकन नहीं हो रहा, इससे पहले भी परिभाषाएं बनीं, मूल्य और मोल तय हुए, लेकिन कोई परिपाटी नहीं बनीं। हम हर साल मंडी शहर में बिकते फालसों के आगमन पर याद करते हैं कि जंगल हमें क्या कुछ दे सकता है। लुंगड़ू की बिक्री में जंगल की शीतल जमीन भी महक उठती है या ब्रांस की लाली में शरबत के घूंट या चटनी का चम्मच, अपने साथ एक पूरा बाजार उपस्थित करता है। किन्नौर और पांगी घाटी के चिलगोजे हों या चुपके से निकलती गुच्छी हो, इनकी कीमत के चर्चे पूरे संसार में होते हैं। जंगल दरअसल समझे ही नहीं और न ही इन्हें आर्थिक पेशकश में उगाने की पहल हुई। हम चीड़ को जंगल और इसके इर्द-गिर्द रही कमाई को ही पूर्ण मानते रहे, जबकि जंगल के कई भूगोल, कई अर्थशास्त्र और कई कारनामे हैं। कुल्लू व लाहुल-स्पीति घाटी की ही संभावनाओं को तोलें तो सारा आयुर्वेद यहां की जड़ी-बूटियों की शरण में चला जाता है। अगर चंबा और तमाम ट्राइबल एरिया में जंगल घोषित जमीन की उत्पादकता पर गौर करें, तो बेशकीमती पैदावार के रूप में सीबक थार्न से लेकर केसर तक हमारी पहुंच हो सकती है। कभी इनसानों की बस्तियों के करीब चरागाहें होती थीं, जो अब चीड़ की पत्तियों से आग की भी बन रही हैं। कहना न होगा कि अगर जंगल के भीतर पशु व वन्य प्राणी आहार पट्टिकाएं विकसित कर लें, तो दूध, मांस-मछली जैसे उत्पाद वनों से सदा-सदा के लिए दोस्ती कर लेंगे। हमारा मानना है कि हिमाचल में जंगल और जंगल भूमि का पुनर्गठन होना चाहिए।

जिस परिभाषा की कानूनी दृष्टि से वन विभाग चलता है, वहां एक पेड़ की निशानियों में हजारों संभावनाएं नष्ट हो रही हैं। वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ वानिकी व कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल किए होते, तो वन खेती के परिदृश्य में भविष्य के तर्क और सशक्त होते। अगर वन विभाग बंदरों, सूअरों और नील गाय जैसे वन्य प्राणियों को आश्रय में ले ले, तो ग्रामीण आर्थिकी के लिए यह सौगात होगी। हमने जंगल वहां उगाए हैं, जहां मानवीय विकास के कई विकल्प पैदा हो सकते थे। उदाहरण के लिए कांगड़ा में अगर फॉरेस्ट के तहत ग्रीन टी का उत्पादन जुड़ जाता, तो यह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिमाचल की बेशकीमती पेशकश होती। इसी तरह आबो हवा के अनुरूप जंगलों में तरह-तरह के पौधे, झाड़ियां व फूल उगाए जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जंगल आधारित आर्थिकी का प्रसार हो रहा है। चीन जैसे देश केवल हर्बल उत्पादों से पंद्रह हजार करोड़ का धंधा कर रहे हैं, तो हिमाचल में भी यह संभावना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैनफ (हिबिस्कस कैनाबिनस) नामक पौधे पर काफी तेजी से अध्ययन एवं शोध में पाया गया है कि इसकी खेती अब जंगलों को बादशाहत प्रदान कर सकती है। यह एक तरह की जूट की तरह लकड़ी का विकल्प बन कर, फनिचर और कुछ अति महंगे उत्पादों में प्रयुक्त हो रहा है। ये पौधे कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था और परिस्थितिकीय के लिए एक अत्यंत लाभकारी एवं उपयोगी नकदी फसल के रूप में भविष्य की मांग को पूरा करेगी। कार के डैशबोर्ड, डोर पैनल, इंसुलेशन सामग्री, पशु आहार तथा इसके बीजों से 22 प्रतिशत तक उच्च पौष्टिकता के कारण खाद्य एवं औषधीय उत्पादों के काम आ सकता है। देहरा से एक अप्रवासी हिमाचली अजय सिंह ठाकुर इस पर काफी अनुसंधान कर चुके हैं। उनकी मानें तो हिमाचल में इसकी वन खेती लाखों डालर तक पहुंच सकती है।

बंगाल बन सकता है पूर्व का ग्रोथ केंद्र

हाल ही के चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने दो तिहाई से ज्यादा जनमत प्राप्त कर सरकार का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में यह आशा बलवती हुई है कि पश्चिम बंगाल पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त कर विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 1.63 लाख रुपए थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 2.05 लाख रुपए था। इस प्रकार, वर्ष 2024-25 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 79.5 प्रतिशत रही, और राष्ट्रीय स्तर पर सालाना प्रतिव्यक्ति आय और पश्चिम बंगाल में प्रतिव्यक्ति आय में 42000 रुपए का अंतर रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं रही। वर्ष 1960-61 में पश्चिम बंगाल की प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 127.5 प्रतिशत थी। 1970-71 में भी वो राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक थी। लेकिन 1980-81 तक आते-आते उसकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 97 प्रतिशत और 2010-11 तक मात्र 84 से 86 प्रतिशत रह गई थी, और यह प्रवृत्ति अभी तक जारी है। 1970 के दशक में जहां भारत की जीडीपी 3.0 से 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही थी, पश्चिम बंगाल की जीडीपी वृद्धि दर सिर्फ 1.5 से 2.0 प्रतिशत ही थी। 1980 के दशक में हालांकि पश्चिम बंगाल में जीडीपी ग्रोथ 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गई, लेकिन औद्योगिक विकास की गति अत्यंत धीमी रही। 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल की वृद्धि दर राष्ट्रीय संवृद्धि दर से अधिक थी।

2000 से लेकर 2011 के बीच हालांकि औद्योगिक उठाव तो नहीं आया, लेकिन सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण पश्चिम बंगाल ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। 2011 और 2025 के बीच भी पश्चिम बंगाल की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से कम थी, और यह 6.5 से 7.0 प्रतिशत रही। चूंकि पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से कम गति से विकास कर रहा था, देश की कुल जीडीपी में इसका हिस्सा 1960 में 10.5 प्रतिशत से घटता हुआ वर्ष 2024-25 में मात्र 5.6 प्रतिशत रह गया। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में सेवा क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, ट्रांसपोर्ट और सरकारी खर्च की बदौलत जीडीपी में वृद्धि तो हुई लेकिन गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कई नए औद्योगिक प्रदेशों की तुलना में पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास अत्यंत धीमा रहा। गौरतलब है कि 1970 और 1990 के बीच में पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा नुकसान औद्योगिक गिरावट के कारण हुआ, जिसके चलते पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत की जीडीपी में नीचे गिर गया। उसके उपरांत पश्चिम बंगाल में जीडीपी ग्रोथ पहले से बेहतर होने के बावजूद, पश्चिम बंगाल का हिस्सा राष्ट्रीय जीडीपी में कम बना रहा। प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम बंगाल पुनः अपना वह गौरव प्राप्त कर पाएगा? क्या एक समय का

औद्योगिक राज्य, जहां अन्यान्य कारणों से उद्योग विमुख हो गए, पुनः उद्योगों की स्थापना कर पाएगा? क्या पश्चिम बंगाल की प्रतिव्यक्ति आय जो आज राष्ट्रीय औसत का मात्र 79.5 प्रतिशत ही है, पुनः राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे ज्यादा हो पाएगी? ये सभी यक्ष प्रश्न देश के सामने हैं और भाजपा की नवगठित सरकार के सामने यह चुनौती भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि एक राज्य जो पूर्व में आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्यों में से एक था, जहां प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 27 प्रतिशत से भी ज्यादा बेहतर थी, उसे वापस पटरी पर कैसे लाया जाए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की आर्थिक बदहाली के कारणों की जांच करनी होगी और उनके समाधान का खाका तैयार करना होगा। यह भी स्पष्ट है कि जब आर्थिक गिरावट आती है तो न तो एक कारण होता है और न ही एक समाधान। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक बदहाली का कारण वहां औद्योगिक क्षेत्र के विकास में व्यवधान रहा। औद्योगिक विकास हेतु सर्वप्रथम इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी होता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पश्चिम बंगाल काफी पिछड़ गया। सडक, बिजली आदि का तो अभाव रहा ही, साथ ही औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन भी न्यूनतम रहा। गौरतलब है कि पूर्व में साम्यवादी शासन में निवेश घटा और निवेशक हड़ताल और श्रम विवादों के चलते पश्चिम बंगाल से विमुख हो गए।

जब पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने टाटा को सिंगूर में नैनो कार प्लांट लगाने की इजाजत देकर पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश की, तो इस बार विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने टाटा को जमीन देने के खिलाफ आंदोलन कर दिया, जिसके कारण वो प्रस्तावित कारखाना टाटा ने गुजरात स्थानांतरित कर दिया। हालांकि यह विवाद तो मीडिया की चर्चा में रहा, लेकिन पिछले 60-70 सालों में ऐसे कई अवसर आए, जिसके कारण उद्योग पश्चिम बंगाल से विमुख होते गए। बिरला, टाटा आदि समेत कई उद्योग समूहों ने अपना मुख्यालय कोलकाता से अन्य स्थानों की ओर स्थानांतरित कर दिया। श्रम विवादों के राजनीतिकरण और आधुनिकीकरण और ऑटोमेशन की खिलाफत ने राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में यह समझना होगा कि पश्चिम बंगाल अपने भूगोल, मानव संसाधनों एवं सांस्कृतिक और औद्योगिक परंपराओं के चलते औद्योगिकीकरण के लिए अत्यंत उपयुक्त राज्य है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी देन है, जो आसियान देशों के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापार का प्रमुख द्वार बन सकता है। कृषि की उच्च उत्पादकता, कोलकाता जैसा शहर और उस पर पढ़ी-लिखी जनसंख्या पश्चिमी बंगाल को ग्रोथ हब बना सकता है। यदि शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बने और मैट्रो कनैक्टिविटी हो सके तो कोलकाता को एक आईटी हब के नाते विकसित किया जा सकता है। यहां उच्च कोटि और अधिक उत्पादकता वाली कृषि के चलते बागवानी, मछली पालन और फूलों के उत्पादन की संभावनाएं हैं ही, और साथ ही साथ यदि वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगें, और कोल्ड चेन को मजबूत किया जाए और निर्यात को बढ़ावा मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी को बढ़ाने में एक बड़ी छलांग लग सकती है। कौशल विकास और श्रम सुधार पश्चिम बंगाल के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। हमें वहां औद्योगिक संबंधों के लिए वातावरण को बेहतर करना होगा और साथ ही महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को भी बढ़ाना होगा। साम्यवादी शासन के दौरान शासक वर्ग की विचारधारा का बड़ी कंपनियों के प्रति संशय का भाव, नियामक वातावरण और विकास से पहले ही पुनर्वितरण के प्रयासों ने विकास को नुकसान पहुंचाया। परंपरागत उद्योगों के ह्रास ने भी पश्चिम बंगाल के विकास को बाधित किया। खासतौर पर तब जब नए उद्योगों का प्रादुर्भाव वहां नहीं हो पाया। सरकार बदलने के बाद आज परिस्थिति बदली है और आशा की जा सकती है कि भाजपा की स्थायी सरकार बनने के बाद निवेशक पश्चिम बंगाल की तरफ आकर्षित होंगे। 1991 के बाद अनुकूल वातावरण के कारण अन्य राज्यों को विदेशी और घरेलू निवेश प्राप्त हुआ। इन राज्यों ने आईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। लेकिन पश्चिम बंगाल इस प्रकार के निवेश को आकर्षित नहीं कर पाया और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता नहीं दी। सरकार को विभिन्न प्रकार के अनुपादक खर्चों को कम करते हुए पूंजीगत खर्च को बढ़ाना होगा, प्रशासन में डिजीटलीकरण बढ़ाकर सरकारी धन के रिसाव को कम करना होगा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़िशें और सुंदरवन के प्राकृतिक टूरिज्म को तो बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक ब्रांड के रूप में विकसित करना होगा।

डा. अश्वनी महाजन, पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रशासनिक मुस्तैदी से ही सुरक्षित होंगे फुटपाथ

उच्चतम न्यायालय ने 19 जून को अपने एक ऐतिहासिक दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया है कि सीमांकित फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने आवागमन और जीवन के अधिकार संबंधी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क), अनुच्छेद 19(1)(ख) और अनुच्छेद 19(1)(ग) के तहत पैदल यात्रियों के अधिकार को सर्वोपरि घोषित करते हुए मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता देने का निर्देश केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को दिया है और इसे सभी स्थानीय निकायों तक पहुंचाने को भी कहा है।

यह दिशा-निर्देश एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में आया है, जिसे अपने पिता के साथ स्कूल जाते समय एक ट्रक ने कुचल दिया था। देखा जाए, तो देश में फुटपाथ की स्थिति बहुत ही खराब है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,000 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 35,000 पैदल यात्री थे, यानी हर पांच में एक व्यक्ति पैदल शिकार हुआ। फुटपाथ न होने के दुष्प्रभाव बहुत व्यापक हैं। उत्पादकता, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण पर इसका खास असर पड़ता है। सड़कों पर मिट्टी जमा होती है, वहां से कूड़ा नहीं उठता, गाड़ियों के लिए कम जगह बचती है। इसका कारण है कि जिनके मकान हैं, वे फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरे, बिजली विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों के ट्रांसफॉर्मर जहां-तहां फुटपाथ पर ही रखे मिलते हैं। फुटपाथ का पार्किंग, धार्मिक स्थल और स्कूलों द्वारा अतिक्रमण तो है ही, हॉकर और रेहड़ी-पटरी वाले भी इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इन कारणों से सड़क पर चलने वालों को असुविधा होती है। इनमें भी महिलाएं, बच्चे और दिव्यांग जन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

असल में, यह पूरा विषय स्थानीय निकायों का है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन

और राजमार्ग मंत्रालय की भी भूमिका है। इस तरह यह अंतर-सरकारी कार्रवाई का विषय बन जाता है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 अक्तूबर को भी एक अन्य मामले में पैदल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जो काफी व्यापक है। इसमें देश के 50 शहरों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे इस बारे में कार्ययोजना बनाएंगे। उसमें पैदल यात्रियों की समस्या और पैदल चलने के बुनियादी ढांचों- जैसे ओवरब्रिज, अंडरपास, क्रॉसिंग आदि के हॉटस्पाट को चिह्नित करना, प्रमुख स्थलों के बारे में कार्ययोजना बनाना शामिल है। इसलिए, जब हालिया निर्देश पर कार्रवाई हो, तो पिछले साल के निर्देशों का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात जान-माल की सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त उत्पादकता, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुनियोजित ढंग से कोर्ट के निर्देशों का पालन होना चाहिए।

एजेंसियों को देखना चाहिए कि फुटपाथ कहां नहीं हैं? जहां नहीं हैं, वहां बनाया जाना चाहिए। जहां वे अतिक्रमण के शिकार हैं, वहां उनको खाली कराया जाना चाहिए। दिल्ली जैसे महानगर में जो फ्लाईओवर बने हैं, उन पर भी फुटपाथ के लिए जगह आवंटित नहीं है। इससे लोग सड़क पर आते हैं या गाड़ी वाले लोग भी फुटपाथ पर चले जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। हालांकि, 1980 के मोटर वाहन कानून की धारा 201 और 210बी में फुटपाथ पर गाड़ी चलाने पर दंड का प्रावधान है, मगर इसे कोई नहीं मानता। विकसित देशों में फुटपाथ की व्यवस्था है और जन जागरूकता उच्च स्तर की है। वहां बुनियादी ढांचा मजबूत है। समस्याओं पर काबू पाया गया है।

हमारे यहां फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और नागरिक, दोनों स्तरों पर उदासीनता रही है। इसलिए फुटपाथ का सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से होना चाहिए। साथ ही ह्यस्टैंडर्ड ऑपरेटिंगह्ल बिंदु बनाकर स्थानीय निकाय को लागू करने चाहिए। इस स्थिति से उबरने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। जब तक जन-सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम कितने भी कानून बना लें, उनका क्रियान्वयन सफल नहीं हो पाएगा। इसमें हमारे राजनेता और अफसर आते हैं। उनकी भी सकारात्मक भूमिका और समझ बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई प्रभावी सुधार नहीं हो सकता है।

के के पांडेय, नगर प्रबंधन विशेषज्ञ
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुस्लिम महिलाएँ और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका

राष्ट्रों की उन्नति और पतन केवल राजनीतिक नेतृत्व या आर्थिक संसाधनों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका शामिल होती है। विशेष रूप से महिलाएँ, जो किसी भी समाज की आधी आबादी होती हैं, यदि सक्रिय, शिक्षित और जागरूक हों तो राष्ट्र विकास की राह पर आगे बढ़ता है। मुस्लिम महिलाओं ने भी इतिहास के हर दौर में, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में, राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उनका यह योगदान केवल घरेलू दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान समय की राजनीति, शिक्षा, सामाजिक सेवा, विज्ञान और संस्कृति तक फैला हुआ है। इस्लाम ने भी महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया: "इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज. है।-इब्न माजा। यह हदीस स्पष्ट करती है कि इस्लाम में महिलाओं की शिक्षा को भी पुरुषों की तरह आवश्यक माना गया है, क्योंकि शिक्षित महिलाएँ ही एक जागरूक और मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकती हैं।

मुस्लिम महिलाओं की सेवाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इतिहास के विभिन्न कालखंडों का अध्ययन करें, विशेष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान समय तक, और उन महान महिलाओं का उल्लेख करें जिन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि महिलाएँ किसी भी राष्ट्र के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, उस समय मुस्लिम महिलाओं ने न केवल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया बल्कि कई अवसरों पर नेतृत्व भी किया। इनमें सबसे प्रमुख नाम बेगम हजरत महल का है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। वे केवल एक साहसी महिला ही नहीं थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी थीं। इसी प्रकार आबिदा बानो बेगम ने खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनसभाओं में भाषण देकर मुसलमानों को जागृत किया और महिलाओं को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता आंदोलन की एक अन्य महान हस्ती अरुणा आसिफ अली थीं, जिन्होंने जन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का संदेश दिया। इसी तरह बेगम रुकैया ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए और महिलाओं के अधिकारों की जोरदार वकालत की।

स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिम महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जारी रखा। उदाहरण के तौर पर फातिमा शेख भारत की प्रारंभिक मुस्लिम महिला शिक्षिकाओं में गिनी जाती हैं, जिन्होंने दलित और मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।वर्तमान समय में भी मुस्लिम महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में संगति प्रदान कर रही हैं। सायरा शाह हलीम, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय हैं, जबकि नजमा हेपतुल्लाह ने राजनीति और अल्पसंख्यक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खेल के क्षेत्र में सानिया मिर्जा मध्यप्रदेश के जिला सिवनी की बेटी नौशीन नाज हाकी टीम में जगह बनाई और निखत जरीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया और यह सिद्ध किया कि मुस्लिम महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी मुस्लिम महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। अनेक सामाजिक और कल्याणकारी संस्थानों में महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। आज के समय में आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस्लाम भी महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहित करता है। पवित्र कुरआन में कहा गया है: है: मोमिन पुरुष और मोमिन महिलाएँ एक-दूसरे के सहायक हैं। अनुमोदित सूरह अत-तौबा : 71। इस आयत से स्पष्ट होता है कि समाज के निर्माण, सुधार और विकास में पुरुष और महिलाएँ दोनों समान रूप से प्रस्तावित हैं। जब महिलाएँ सशक्त होंगी, तब वे न केवल स्वयं प्रगति करेंगी बल्कि पूरे राष्ट्र को भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएँगी अंत में यह कहना उचित होगा कि मुस्लिम महिलाएं केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति भी हैं। ऐतिहासिक गवाह है कि उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, राजनीति, साहित्य, खेल और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास से समाज में एक विशेष स्थान बनाया है। आज भी मुस्लिम महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति में योगदान दे रही हैं। वे डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेताओं के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रही हैं। इस्लाम ने भी महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें समान अवसर, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए, ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। जब महिलाएं शिक्षित और सशक्त होंगी, तब परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों मजबूत बनेंगे। इसलिए मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सूफी समाजिक कार्यकर्ता
सूफी मंजूर रजा कादरी
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लब्बैक यूथ फोर्स आतंकवाद विरोधी संगठन सिवनी मध्यप्रदेश इंडिया

आलेख

भाजपा को अब भी छका रहा दक्षिण

भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण अभियान में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। केरल और तमिलनाडु के हालिया विधानसभा चुनावों में प्रभावशाली छाप न छोड़ पाने से उसके नेताओं-कार्यकताओं में निराशा फैल रही है। चुनाव के कुछ ही दिनों बाद तमिलनाडु में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य में उसके सबसे लोकप्रिय नेता के अन्नामलाई ने राजी-खुशी उससे किनारा कर लिया, उसके बाद कई अन्य नेताओं ने भी सत्तारूढ़ टीवीके का रुख कर लिया। अब कर्नाटक से उसके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही।

तमिलनाडु और केरल में पैठ बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी मुश्किल रहा है, लेकिन कर्नाटक में उसे जिस विरोध का सामना करना पड़ा है, वह निश्चित रूप से उसके लिए एक झटका है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा दक्षिणी राज्य है, जहां वह अपनी सरकार बनाने में सफल रही और यह राज्य उसके लिए दक्षिण भारत का प्रवेश-द्वार साबित हुआ है। इसी तरह, पार्टी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पैठ बनाने में मुश्किलें हो रही हैं। दक्षिण में पार्टी को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन इलाकों में हिंदुत्व या ध्रुवीकरण की राजनीति को बहुत कम पसंद किया जाता है। हालांकि, पार्टी धीरे-धीरे इन राज्यों में आगे बढ़ रही है, पर कर्नाटक को छोड़कर किसी अन्य सूबे में वह स्थिति को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने से बहुत दूर है। ऐसे में, कर्नाटक का नया घटनाक्रम उसके लिए चिंता का सबब होना चाहिए।

दरअसल, दल-बदल, विलय और इस्तीफे की समस्या अब विपक्षी दलों तक सीमित नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी में भी यह घुस गई है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में सबसे पसंदीदा राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरने का जश्न मना रही भाजपा को शायद अब एहसास हो रहा है कि दक्षिण में उसका घर भी खास मजबूत नहीं है। कर्नाटक में उसकी अपनी पार्टी के भीतर भी यह गड़बड़ी फैल चुकी है।

देश भर में ह्यऑपरेशन लोटसह्न का सीधा-सा अर्थ समझा जाता है- विपक्ष के चुने हुए सांसदों-विधायकों को साम-दाम-दंड-भेद के जरिये अपनी तरफ मिलाना, मगर दक्षिण के इस राज्य में ह्यऑपरेशन हैंडह्न के रूप में एक नई और अप्रत्याशित स्थिति सामने आई है। हालांकि, इन दोनों ऑपरेशनों में अंतर है। जहां एक तरफ देश के बाकी हिस्सों में विपक्षी नेताओं का भाजपा में शामिल होना अप्रिय रणनीति का नतीजा होता है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की किस्मत भाजपा और एनडीए के अंदरूनी झगड़ों की वजह से चमकी है।

बीते 18 जून को हुए कर्नाटक विधान परिषद के चुनावों में कांग्रेस अपनी सदस्य संख्या के बूते चार सीटें जीतने की क्षमता रखती थी, मगर उसने

पांचवीं सीट भी आसानी से हासिल कर ली। जाहिर है, उसे भाजपा और जनता दल (सेकुलर) के विधायकों की क्रॉस-वोटिंग का फायदा मिला। भाजपा ने अपनी तय दो सीटें जीत लीं, मगर इसके बावजूद उसे एक झटका भी लगा। उसे अपनी ही पार्टी के विधायकों से चार वोट कम मिले। जनता दल (एस) के लिए तो यह कहीं ज्यादा बड़ा झटका था। उसका एकमात्र उम्मीदवार हार गया और उसे 14 वोट ही मिल पाए, जबकि विधानसभा में इस पार्टी के 18 विधायक हैं।

जनता दल (एस) ने भाजपा के समर्थन और कांग्रेस विधायकों की क्रॉस-वोटिंग के सहारे यह सीट जीतने का सपना देखा था, मगर जो हुआ, वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। भाजपा और जनता दल (एस), दोनों पार्टियों के विधायकों ने एक-दूसरे का समर्थन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। जाहिर है, भाजपा के केंद्रीय आलाकमान ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं को आज दिल्ली तलब किया है।

क्रॉस-वोटिंग के अलावा कर्नाटक में भाजपा के साथ जो हुआ और उत्तर भारत में विपक्ष के साथ उसने जो किया, उन दोनों के बीच तुलना करने लायक बहुत कम बातें हैं। कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव थे। मध्य प्रदेश और झारखंड के राज्यसभा चुनावों में जो कुछ हुआ और पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायक व संसदीय दल में टूट और उद्धव की शिवसेना में फूट ने लोगों का ध्यान अधिक खींचा। इन सबमें कर्नाटक की क्रॉस वोटिंग की बात दब गई। वैसे, विपक्ष में और भी टूट-फूट हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 362 सांसदों की जरूरत है, ताकि वह अपने इरादे वाले कानून पारित करा सके। टूट की शिकार आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर और लोभ की वजह से ये नेता पार्टी छोड़ रहे हैं।

कर्नाटक में जो हुआ, वह बिल्कुल अलग मामला था। यहां तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बिना किसी कोशिश के ही एक बड़ा फायदा मिल गया है। अपनी-अपनी पार्टी के राज्य नेतृत्व से नाराज भाजपा-जनता दल (एस) विधायकों ने क्रॉस वोटिंग के कदम उठाए हैं। इनमें भी भारतीय जनता पार्टी का मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। गुटबाजी से जूझ रही पार्टी की राज्य इकाई के नेता प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की बात मानने को तैयार नहीं हैं। विजेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक अपने सदस्यों पर पकड़ मजबूत नहीं बना सके हैं। दरअसल, राज्य भाजपा के बहुत सारे नेता विजेंद्र को ऊपर से थोपा हुआ नेता मानते हैं। भाजपा उत्तरी कर्नाटक से लिंगायत वोट दिलाने के लिए येदियुरप्पा की एहसानमंद है, लेकिन उनके बेटे अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं।

दूसरी ओर, जनता दल (एस) को अंदरूनी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके कुछ सदस्य वोक्कालिगा समुदाय के डीके शिवकुमार के शासन का समर्थन करने के इच्छुक हैं। कुमारस्वामी अपने समर्थकों में जोश नहीं भर पा रहे हैं। जनता दल (एस) के नेता ने सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा व्यक्त की है, मगर भाजपा आश्चर्यजनक रूप से शांत है। विजेंद्र को बाहर करने की मांग के बीच हाईकमान ने ह्यसमीक्षाह्न की बात कही है, मगर भाजपा की दुविधा यह है कि वोक्कालिगा समर्थन अब कांग्रेस के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है, अगर वह येदियुरप्पा को नाराज करने वाला कोई कदम उठाती है, तो उसे लिंगायत वोटों का भी नुकसान होगा। भाजपा के लिए दक्षिण वाकई दुरूह है।

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दिल्ली के तकिया काले खान के पास भीषण आग से 30 झुग्गियां जलकर खाक

दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे तकिया काले खान इलाके की वाल्मीकि बस्ती में बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। साथ ही बड़ी मात्रा में प्लाईवुड, लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री भी नष्ट हो गई।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आग की तीव्रता के बावजूद आपातकालीन सेवाओं और पुलिसकर्मियों की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार रात करीब 11:32 बजे तकिया काले खां इलाके में आग लगने की पीसीआर कॉल मिली। स्थानीय पुलिस टीमें स्थिति का आकलन करने और बचाव एवं निकासी अभियान शुरू करने के लिए मौके पर पहुंचीं। भीषण आग ने वहां संग्रहीत पुराने फर्नीचर, लकड़ी, प्लाईवुड और अन्य अत्यधिक दहनशील सामग्रियों के एक बड़े भंडार को अपनी चपेट में ले लिया था। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे आसपास की झोपड़ियों और घनी आबादी में रहने वाले निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ।

पुलिसकर्मियों ने तुरंत निकासी अभियान चलाया और स्थानीय निवासियों को तेजी से फैल रही आग से उत्पन्न खतरे के बारे में सचेत किया। अधिकारियों ने कहा कि कुछ निवासियों के प्रतिरोध के बावजूद, जो अपने घरों और सामान को पीछे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के अपने प्रयास जारी रखे। त्वरित हस्तक्षेप के माध्यम से, पुलिस टीमों ने पूरे संवेदनशील क्षेत्र को सफलतापूर्वक खाली करा लिया और कई परिवारों के सदस्यों सहित 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इसके साथ ही, घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग, बीएसईएस और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को दी गई, जिन्होंने तेजी से मामले की गंभीरता को समझा और साइट पर आपातकालीन संसाधन तैनात किए। अधिकारियों ने कहा कि आग से निपटने के लिए कुल 20 दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया था, जबकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एहतियात के तौर पर नौ कैट्स एम्बुलेंस को मौके पर मौजूद रहीं। अतिरिक्त रिजर्व पुलिस कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे और निकासी प्रयासों, भीड़ नियंत्रण उपायों और फायर टेंडर, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए स्पष्ट पहुंच मार्ग बनाए रखने में सहायता की। अग्निशमन कर्मियों ने लगभग तीन घंटे के बाद आग पर काबू पाया और अंततः उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया। ऑपरेशन रात भर जारी रहा। अधिकारियों के अनुसार, निवासियों की समय पर निकासी, अग्निशमन संसाधनों की तेजी से तैनाती और सभी एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय ने यह सुनिश्चित किया कि आग की भयावहता और संपत्ति को हुए व्यापक नुकसान के बावजूद कोई जान का नुकसान न हो और कोई घायल न हो। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और आगे की जांच जारी है।

संक्षिप्त वार्ता

अग्निकांड पीड़ितों की सहायता के लिए भाजपा हर संभव कदम उठाएगी: हर्ष मल्होत्रा

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली गेट वार्ड स्थित बाल्मीकि बस्ती में कल देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग से कई परिवारों के घर और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इस दुखद घटना के बाद मंगलवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, क्षेत्रीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल, चांदनी चौक जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग एवं दिल्ली भाजपा कार्यालय सह प्रमुख अमित गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों एवं दुकानदारों से मुलाकात कर राहत कार्यों में सहयोग किया।

इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 15 परिवारों के आशियाने उजड़ गए। परिवारों ने अपना घर और सामान खोया है, उनके दुख में भाजपा उनके साथ खड़ी है। आग ने कई परिवारों के घर एवं दुकान को प्रभावित किया है, लेकिन संकट की इस घड़ी में भाजपा कार्यकर्ता और सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वीवो धनशोधन मामले में बड़ा फैसला, दो चीनी नागरिकों के विदेश जाने पर रोक

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवो मोबाइल से जुड़े लगभग 20000 करोड़ रुपये के चर्चित धनशोधन मामले में बड़ा आदेश देते हुए दो चीनी नागरिकों के चीन जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपितों के देश छोड़ने की स्थिति में उनके वापस लौटने की कोई निश्चितता नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के 17 जून के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें आरोपितों को विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है।

मामले के आरोपितों में गुआंगवेन कुआंग उर्फ एंड्रयू और वेइगांग वांग शामिल हैं। गुआंगवेन कुआंग को अक्तूबर में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसे नवंबर में जमानत मिली थी। दोनों आरोपितों के विरुद्ध धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोपपत्र दायर किया जा चुका है।

संजय दत्त समर्थित व्हिस्की ब्रांड पर अदालत की रोक, 'गॉडफादर' नाम के उपयोग पर अंतरिम प्रतिबंध

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता संजय दत्त समर्थित कंपनी कार्टेल ब्रोज को अपनी व्हिस्की के लिए 'गॉडफादर' नाम और उससे मिलते-जुलते किसी भी चिह्न के उपयोग से फिलहाल रोक दिया है।

न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज की अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका स्वीकार करते हुए कार्टेल ब्रोज, उसके निदेशकों, साझेदारों तथा कंपनी की ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को मुकदमे के निस्तारण तक 'गॉडफादर' अथवा उससे मिलते-जुलते किसी भी नाम, लेबल, पैकेजिंग, कार्टन अथवा व्यापारिक पहचान का उपयोग करने से रोक दिया। न्यायालय ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि 'गॉडफादर' नाम से संबंधित सभी प्रचार सामग्री, विज्ञापन, प्रसारण, सूचीकरण और अन्य सामग्री को तत्काल सभी आनलाइन तथा आफलाइन माध्यमों से हटाया जाए। सुनवाई के दौरान देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज ने न्यायालय को बताया कि वह वर्ष 1984 से 'गॉडफादर' नाम का उपयोग कर रही है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और अन्य भाजपा नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने पौधारोपण भी किया।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं हम सभी के प्रेरणास्रोत श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज दिल्ली गेट स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। भारत की अखंडता के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण का अमर प्रतीक है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पार्क में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में साथी कार्यकताओं की उपस्थिति रही। राष्ट्र की सेवा और समर्पण के अमर प्रतीक श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोटि-कोटि नमन। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, ह्लआज, इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर हम भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चाहे हम सरकार में काम कर रहे हों या संगठन में, भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेता आज जिस विचारधारा, नीतियों और विजन के साथ सेवा करते हैं, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी।

हर्ष मल्होत्रा ने कहा, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत को एकजुट रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाया, तो उस बलिदान का सही अर्थ सार्थक हुआ। इसके परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और अब भारत का संविधान सीधे जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। इसी दिन बिना परमिट के कश्मीर में घुसते समय वे घायल हो गए थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। हम उन्हें याद कर रहे हैं और पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।

अपने प्राणों का बलिदान किया

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जो एकता, भारतीय पहचान और राष्ट्रवाद के प्रबल प्रहरी थे। उनका जीवन यह दिखाता है कि ह्राष्ट्र प्रथम केवल एक नारा नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम एक दृष्टिकोण है, एक जीवन दर्शन है। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, आज हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े रहे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रेरित है। दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे महान दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने खुद को हिंदू धर्म और इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने देश सेवा के लिए अपना मंत्री पद तक छोड़ दिया था और देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया।

दिल्ली में एक जनवरी 2025 तक अस्तित्व में रहीं झुग्गी बस्तियों के निवासियों को मिलेगा पुनर्वास का लाभ

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 36वीं बोर्ड बैठक में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार के मुताबिक बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में एक जनवरी 2025 तक अस्तित्व में रही सभी झुग्गी बस्तियों के पात्र निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में झुग्गीवासियों को राहत मिलेगी। इस निर्णय का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

राशिद हत्या मामला

दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी हारून गिरफ्तार

नई दिल्ली, वेब वार्ता

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली पुलिस ने राशिद हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मंगलवार को खजूरी इलाके में सिग्नेचर ब्रिज के पास हुई मुठभेड़ के बाद मामले के मुख्य आरोपी हारून को गिरफ्तार कर लिया।

सूत्रों के मुताबिक, जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को इलाके में हारून की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए एक खास अभियान चलाया गया। जब पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, तो हारून ने भागने की कोशिश की और पुलिस अधिकारियों पर गोली चला दी।

सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पार्टी पर कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी के दौरान हारून के पैर में गोली लगी और बाद में पुलिस ने उसे काबू कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद उसे इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है, हालांकि पुलिस ने अभी तक हथियार और ऑपरेशन के दौरान बरामद अन्य चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

हारून काफी समय से फरार चल रहा था और राशिद के सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी को नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जांचकताओं का मानना है कि आरोपी से पूछताछ करने पर हत्या से जुड़ी और जानकारी मिल सकती है और अपराध में शामिल अन्य लोगों की पहचान हो सकती है। आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस की मुहिम रंग लाई

24 घंटे में दिव्यांग महिला समेत 5 लापता लोगों को परिवार से मिलाया

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की मानव तस्करी निरोधक इकाई ने एक सराहनीय अभियान के तहत दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से चार किशोरों और एक दिव्यांग महिला को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिला दिया। इस अभियान की विशेष बात यह रही कि मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला और सात वर्षीय एक बच्चे को मात्र 24 घंटे के भीतर खोज निकाला गया।

अपराध शाखा के विशेष आयुक्त एचजीएस धालीवाल के अनुसार सहायक पुलिस आयुक्त सुरेश कुमार के नेतृत्व में निरीक्षक मुकेश कुमार और मनोज दहिया की टीम ने आधुनिक निगरानी तकनीक तथा मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह सफलता हासिल की।

पहले मामले में हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र के रहने वाले दस वर्ष और छह वर्ष आयु के दो सगे भाई 10 जून को घर के बाहर खेलते समय रास्ता भटक गए और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर अकेले घूमते पाए जाने पर पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षा में लेकर पहाड़गंज स्थित बाल गृह में रखा था। अपराध शाखा की टीम ने जांच के बाद दोनों बच्चों को वहां से बरामद कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उनके परिवार को सौंप दिया।

दूसरे मामले में स्वरूप नगर क्षेत्र की मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला 11 जून को अपनी बहन के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ता भटक गई। सहायक उपनिरीक्षक अजय कुमार झा ने तकनीकी निगरानी की सहायता से महिला की स्थिति का पता लगाया। महिला पुलिसकर्मियों की टीम महिला के भाई को साथ लेकर मंदिर मार्ग बस अड्डे पहुंची और महज 24 घंटे के भीतर महिला को सकुशल बरामद कर लिया। सत्यापन के बाद महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

तीसरे मामले में 15 वर्षीय एक किशोर को हरियाणा के सोनीपत से बरामद किया गया। 13 जून को लापता हुआ यह किशोर आगे पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन आर्थिक कारणों से परिवार उसकी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ था। इसी कारण वह घर छोड़कर सोनीपत चला गया था। बवाना थाना क्षेत्र की टीम ने उसे खोज निकाला, उसकी काउंसलिंग की और सुरक्षित रूप से परिवार को सौंप दिया। चौथे मामले में बिहार से उपचार के लिए दिल्ली आए सात वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे को भी पुलिस ने खोज निकाला। 20 जून को बच्चा घर के बाहर से लापता हो गया था। सहायक उपनिरीक्षक अजय कुमार झा को एक संदेश समूह के माध्यम से इसकी जानकारी मिली।

पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र की कंपनी में 7.68 करोड़ की साइबर ठगी

नई दिल्ली, वेब वार्ता

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के पुत्र और उद्योगपति नरेश गुजराल की कंपनी से 7.68 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि ठगी की 4.28 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित कर ली गई है।

विशेष शाखा की सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवाएं इकाई ने पंजाब निवासी नवनीत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित ने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था, जिसका उपयोग ठगी की रकम के लेनदेन के लिए किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवाएं इकाई के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि नवनीत को रविवार को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। वह एक निजी कंपनी में कार्यरत था। जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों ने ठगी की रकम को छिपाने के लिए कई स्तरों वाला वित्तीय जाल तैयार किया था। पुलिस जांच के अनुसार, ठगी की पूरी राशि सबसे पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चार बैंक खातों में भेजी गई। इसके बाद कुछ ही मिनटों के भीतर इस धनराशि को दूसरे स्तर के 40 से अधिक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपित नवनीत दूसरे स्तर का खाताधारक है, जिसके खाते में 5 लाख रुपये भेजे गए थे। पुलिस अब पूरे धन हस्तांतरण तंत्र की जांच कर रही है। अन्य खाताधारकों और मुख्य आरोपितों की तलाश में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार छापेमारी की जा रही है।

4.28 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश से मिली राहत

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर बाद चली तेज धूल भरी आंधी के बाद राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने दिल्ली में तेज आंधी, बिजली गिरने और वर्षा को लेकर लाल चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों के दौरान राजधानी के अधिकांश हिस्सों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ वर्षा होने और कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी आने की संभावना है। मंगलवार दोपहर अचानक मौसम बदलने के साथ दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने लगीं। तेज हवाओं के कारण सड़कों पर धूल का घना गुबार छा गया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

आंधी के कारण खुले स्थानों पर रखे सामान उड़ने लगे। कई दुकानदारों को जल्दबाजी में अपना सामान समेटना पड़ा, जबकि राहगीर धूल से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखाई दिए। कुछ क्षेत्रों में दुकानों को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा। धूल का गुबार छंटने के बाद राजधानी के विभिन्न इलाकों में बारिश शुरू हो गई। ठंडी फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बारिश के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और बच्चों तथा युवाओं को सड़कों पर बारिश का आनंद लेते देखा गया। कई लोग इस बदलते मौसम के दृश्य अपने दूरभाष में कैद करते भी नजर आए।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है तथा हल्की से मध्यम वर्षा अगले कुछ घंटों तक जारी रहने की संभावना है। विभाग ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सतर्क रहने तथा आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लोगों से भी खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और विद्युत खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। उधर, राजधानी की वायु गुणवत्ता फिलहाल 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई है। मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। एनसीआर के अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी के बीच बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि निकट भविष्य में इसमें बहुत अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं है।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया में सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के देवरिया- रुद्रपुर मार्ग पर सुगौली थाना क्षेत्र के कोईलगढ़वां गाँव के समीप रविवार की रात दस बजे हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। सुरौली थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के अनुसार देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के गाँव कोईलगढ़वां निवासी प्रदीप गोंड (26) पुत्र स्व सुदामा गोंड अपने गाँव के चौराहे पर सब्जी खरीदने गये थे। रात करीब दस बजे सब्जी खरीद कर वापस पैदल घर आ रहें थे कि देवरिया- रुद्रपुर मार्ग पर एक पुलिया के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी। जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजवाया। जहाँ पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में सुरौली थानाध्यक्ष अविनाश मौर्य ने बताया कि प्रदीप गौड़ की मौत किसी वाहन के चपेट में आने से हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

जेठ के अंतिम बड़े मंगल पर भव्य भंडारा, प्रसाद ग्रहण करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जेठ माह के अंतिम बड़े मंगल के पावन अवसर पर मंगलवार को शहर के मोहल्ला आशा नगर गेट के निकट श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। हरदोई के प्रख्यात पत्रकार रितेश मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित भव्य भंडारे में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से लेकर देर शाम तक प्रसाद ग्रहण करने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं और पूरा क्षेत्र भगवान हनुमान के जयघोषों से गुंजायमान रहा।

हिंदू धर्म में जेठ माह के बड़े मंगल का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसी आस्था और जनकल्याण की भावना के साथ आयोजित इस भंडारे में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर बजरंगबली के चरणों में अपनी आस्था अर्पित की तथा परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की प्रार्थना की। भंडारे के आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण देखते ही बन रहा था। एक ओर श्रद्धालु भजन-कीर्तन और हनुमान जी के जयकारों में लीन दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर स्वयंसेवक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रसाद वितरण में जुटे रहे। श्रद्धालुओं को पूड़ी, सब्जी, छोले, चावल, बूंदी सहित विभिन्न व्यंजनों का प्रसाद प्रेमपूर्वक वितरित किया गया। आयोजन के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई। स्थानीय गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों, व्यापारियों तथा क्षेत्रवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आयोजन की सराहना की। लोगों ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, सहयोग और सौहार्द की भावना को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

आयुष चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर सख्त हुए डीएम, 18 अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जनपद में आयुष सेवाओं को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आयुष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुष विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी आयुष चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही आयुष औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने, चिकित्सालयों में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

आरटीओ कार्यालय में नहीं है फायर सेफ्टी सिस्टम, हो सकती है बड़ी अनहोनी

सारथी लाइसेंस भवन में वर्ष 2023 में लगे थे सिर्फ दो उपकरण, जो नाकाफी

वेब वार्ता, कानपुर। लखनऊ के एक संस्थान में हुए भयानक अग्निकांड में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद परिवहन विभाग की नींद टूटी है। परिवहन विभाग के मुखिया, परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के सख्त निर्देश के बाद अब प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आदेश मिलते ही कानपुर के संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) प्रशासन, राकेंद्र कुमार सिंह ने तत्काल मण्डल के 6 जिलों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर अग्निशमन यंत्रों की स्थिति की जानकारी तलब की है।

कानपुर आरटीओ सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति

कानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) परिसर की जमीनी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ न तो कोई आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है और न ही आपातकाल के लिए कोई फायर अलार्म। कई अधिकारी आए और गए, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किसी ने नहीं किए। कागजों

में सुरक्षा वर्ष 2023 में सारथी लाइसेंस भवन में महज दो अग्निशमन उपकरण टांगे गए थे, जो इस विशाल परिसर और यहाँ आने वाली भीड़ के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। अगर यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा बैठक

अग्नि सुरक्षा के इस बेहद संवेदनशील मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गंभीर हैं। वे 5 कालिदास मार्ग स्थित सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में सभी सरकारी विभागों से अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, उनके रख-रखाव और वर्किंग कंडीशन की विस्तृत रिपोर्ट तलब की जाएगी।

क्या कहता है नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) का नियम

एनबीसी के नियमानुसार, किसी भी सार्वजनिक या सरकारी कार्यालय में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आरटीओ कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोग अपने काम के लिए आते हैं, साथ ही यहाँ भारी मात्रा में गाड़ियों और लाइसेंस से

जुड़े कागजी रिकॉर्ड (फाइलें) मौजूद रहते हैं। नियमों के मुताबिक, यहाँ निम्नलिखित व्यवस्थाएं होना अनिवार्य है जिसमें फायर एनओसी, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, फायर अलार्म व हाइड्रेंट पूरे परिसर में चालू हालत में अलार्म और पानी की बौछार वाले हाइड्रेंट सिस्टम, प्रशिक्षित स्टाफ आपात स्थिति में उपकरणों को चलाने के लिए कार्यालय के कर्मियों का प्रशिक्षित होना। वैधता लगे हुए सिलेंडरों की नियमित रीफिलिंग और उनकी एक्सपायरी डेट दुरुस्त होना।

परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश भर के सभी उप परिवहन आयुक्तों को निर्देश जारी कर उनके क्षेत्रों के अधीन संचालित सभी विभागीय परियोजनाओं की रिपोर्ट मांगी है। इनमें आईडीटीआर, डीटीटीआई, एटीएम, एडीटीसी शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन केंद्रों पर लगे फायर उपकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जाए।

लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में सख्ती, 40 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस

कानपुर। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुई आग की घटना के बाद कानपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आ गए हैं। मंगलवार को पुलिस कमिश्नरेट में कोचिंग सेंटर, होटल, हॉस्टल, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और अन्य व्यावसायिक भवनों के संचालकों के साथ बहु-विभागीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकासी, भवन सुरक्षा और अन्य मानकों के शत-प्रतिशत अनुपालन पर जोर दिया गया।

डॉ. मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल को मिला अत्याधुनिक पोर्टेबल वेंटिलेटर

हरि शंकर शर्मा, वेब वार्ता

कानपुर। मरीजों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डॉ. मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल को मंगलवार को एक अत्याधुनिक पोर्टेबल वेंटिलेटर समर्पित किया गया। यह वेंटिलेटर ₹बायोस क्लिनिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित और ₹श्री खाटू श्याम चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया

गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इस पोर्टेबल वेंटिलेटर की उपलब्धता से आपातकालीन इकाई अब और अधिक सुदृढ़ एवं पूर्णतः सुसज्जित हो गई है। विशेष रूप से टीबी, सीओपीडी , अस्थमा एवं अन्य गंभीर श्वसन रोगों से पीड़ित मरीजों को आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत वेंटिलेटरी सहायता दी जा सकेगी।

चेस्ट हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष डॉ. अवधेश कुमार ने बताया यह वेंटिलेटर इनवेसिव और नॉन-इनवेसिव दोनों सुविधाओं से युक्त है। इससे गंभीर श्वसन संकट वाले मरीजों के उपचार में डॉक्टरों को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। इस सुविधा के जुड़ने से आपातकालीन सेवाएं और अधिक सक्षम होंगी और रोगियों को समय पर जीवनरक्षक उपचार मिल सकेगा। इस अवसर पर एल.एल.आर. (हैलट) अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल, प्रोफेसर डॉ. आनंद कुमार, प्रोफेसर डॉ. संजय कुमार, डॉ. लक्ष्मी, डॉ. अर्पिता, डॉ. अखिल, विभाग के रेजिडेंट चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। साथ ही बायोस क्लिनिकल सर्विस प्रा. लि. के निदेशक डॉ. शैलेश सिंह तथा श्री खाटू श्याम चौरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी प्रियांशु तिवारी व शिवांशु तिवारी भी उपस्थित रहे।

दहेज में बुलेट न मिलने पर नहीं आई बारात, दूल्हे समेत सात पर मुकदमा

वेबवार्ता, हरदोई

जिले के सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में दहेज की कथित मांग को लेकर एक शादी ऐन वक्त पर टूट गई। जिस घर में शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां बारात न आने से खुशियों की जगह मायूसी छा गई। आरोप है कि दूल्हा बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पर अड़ गया और मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दूल्हे समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सवायजपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का विवाह फरुर्खाबाद जिले के जिराऊ गांव निवासी इन्द्रपाल सिंह के पुत्र आकाश सिंह के साथ तय हुआ था। परिजनों के अनुसार, 19 मार्च को वरीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इसके बाद 17 जून को आयोजित तिलक समारोह में दुल्हन पक्ष ने पांच लाख रुपये नकद, दो सोने की अंगूठियां और करीब दो लाख रुपये का अन्य सामान दिया था। परिवार ने विवाह की तैयारियों पर भी लाखों रुपये खर्च किए थे।

21 जून को बारात आनी थी। इसके लिए दुल्हन पक्ष ने 1.10 लाख रुपये किराये पर गेस्ट हाउस बुक कराया था। विवाह स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और बारातियों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। हलवाई कई दिनों से पकवान बनाने में जुटे थे। रिश्तेदार और मेहमान भी पहुंच चुके थे। पूरे परिवार को बेटी की शादी का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी बारात नहीं पहुंची। पहले लोगों ने इसे सामान्य देरी समझा, लेकिन देर रात तक कोई सूचना न मिलने पर चिंता बढ़ गई। काफी इंतजार के बाद दुल्हन के पिता ने दूल्हे के पिता इन्द्रपाल सिंह को फोन किया। आरोप है कि उन्हें बताया गया कि दूल्हा कहीं चला गया है, इसलिए बारात नहीं आएगी।

परिजनों का कहना है कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि दूल्हा आकाश सिंह बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और मांग पूरी न होने के कारण उसने विवाह से इनकार कर दिया। यह सुनते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। जिस मंडप में वैवाहिक रस्में होनी थीं, वह सूना रह गया और मेहमान स्तब्ध रह गए।

घटना से आहत दुल्हन के पिता ने सवायजपुर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दूल्हा आकाश सिंह, उसके पिता इन्द्रपाल सिंह, मां प्रविता सिंह, भाई विशाल सिंह, मनी तथा विवाह तय कराने वाले दो बिचौलियों विवेक और राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

खड़े कर दिये हैं सवाल

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दहेज की कथित मांग को लेकर टूटी यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं, घटना ने एक बार फिर दहेज जैसी सामाजिक कुरीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिवानंद को न्याय दिलाने के पक्ष में चल रहे सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अमेरिकी हमले में मारे गए शिवानंद चौरसिया के परिवार को न्याय दिलाने के लिए चल रहे न्याय सत्याग्रह स्थल पर सोमवार की शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार को परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार शिवानंद चौरसिया की हत्या को स्वीकार करने से बच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक शिवानंद चौरसिया तथा उनके साथ मारे गए दो अन्य भारतीय नागरिकों की मृत्यु का उल्लेख तक नहीं किया है। अजय राय ने इसे केंद्र सरकार की कूटनीतिक विफलता बताते हुए कहा कि यह केवल तीन भारतीय नागरिकों की मृत्यु का प्रश्न नहीं है, बल्कि खाड़ी देशों में कार्यरत करोड़ों भारतीय श्रमिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा तथा भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। इसके बाद उन्होंने सुरौली गांव में पहुंच कर शिवानंद के पिता व अन्य परिजनों से भी मुलाकात की।

हरदोई रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते मिले तीन बच्चे, टीम ने किया रेस्क्यू

हरदोई, 23 जून। बाल भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, एएचटीयू एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान भीख मांग रहे तीन बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 22 जून को चलाए गए अभियान में संरक्षण अधिकारी शैलेन्द्र पाठक, रामू यादव, कंचन गुप्ता और बिरेन्द्र शुक्ला सहित पुलिस एवं महिला आरक्षी मौजूद रहे।

कुशीनगर में किलकारी हास्पिटल के डॉक्टर की गुंडई वीडियो वायरल

वीडियो के बाद सामने आई लिखित शिकायत

वेब वार्ता, कुशीनगर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना में अपने चिकित्सकीय दायित्वों से इतर व्यवहार कर मरीजों एंव उनके परिजनों के साथ मारपीट व विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले किलकारी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. कमलेश वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चर्चा की वजह हर बार की तरह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें अस्पताल परिसर में हंगामे जैसे माहौल के बीच डॉ कमलेश वर्मा हाथ में तमंचा लेकर कुछ लोगो के साथ धक्का-मुक्की और तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।चिकित्सकों को ₹धरती का भगवान₹ मानने वाले लोग भी इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है।

वायरल वीडियो के बीच अधिवक्ता संकल्प चतुर्वेदी द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत ने मामले को और गंभीर बना दिया है। शिकायत के अनुसार, पेट की पथरी की जांच के लिए कराए गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद विवाद शुरू हुआ। तहरीर मे संकल्प चतुर्वेदी ने कहा है कि जब वह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर संबंधित डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर न होने का कारण पूछा तो डॉ. कमलेश वर्मा भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए अपने हाथ में तमंचा लेकर दौड़ा दिया और धमकी दी कि ₹तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरा सम्बन्ध बड़े-बडे अधिकारियों से है।₹शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि मौके पर मौजूद स्थानीय लोग बीच-बचाव न करते तो कोई बड़ी घटनी घट सकती थी। बाद में लोगों ने कथित तौर पर डॉक्टर के हाथ से तमंचा भी छीन लिया और पीड़ित किसी तरह अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंचा। शिकायत में गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जानी है।

वायरल वीडियो और शिकायत पत्र के बाद मामला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक अस्पताल का नहीं, बल्कि चिकित्सा पेशे की गरिमा और मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल बन जाएगा।

पुराने विवादों की लंबी फेहरिस्त

स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि किलकारी हॉस्पिटल और उसके संचालक डॉ. कमलेश वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी अस्पताल परिसर में मरीज के परिजनों के साथ हॉकी से मारपीट का मामला सुर्खियों में रहा था। उस घटना के वीडियो और चचाओं ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी।क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लगभग हर वर्ष किसी न किसी मरीज, तीमारदार या परिजन के साथ विवाद, अभद्र व्यवहार, मारपीट या तीखी नोकझोंक को लेकर डॉ. वर्मा चर्चा में बने रहते हैं। यही वजह है कि ताजा शिकायत सामने आने के बाद लोगों के बीच फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर चल रहे संस्थानों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वीडियो ने पुराने मामलों की याद भी ताजा कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर एक चिकित्सक, जिसकी पहचान सेवा और संवेदनशीलता से होनी चाहिए, उसका नाम बार-बार विवादों से क्यों जुड़ रहा है?

देवरिया में दोबारा आगामी 26 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने प्रस्तावित आगमन

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरांव पहुंची और प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 26 जून को प्रस्तावित है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

अधिकारियों ने पकड़ी-बरांव मार्ग के समीप प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, मंच व्यवस्था, जनसभा स्थल, हेलिपैड और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान डीएम मधुसूदन हुल्गी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था तथा आमजन की सुविधा से जुड़े सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को संवेदनशील बिंदुओं की पहचान कर सुरक्षा योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी।

महत्वपूर्ण ख़बर

डंपर सहित सतलुज में जा गिरा लोहे का पुल, टापरी-चोलिंग सडक बंद

- रिकांगपिओ। किन्नौर जिला में टापरी-चोलिंग के बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 पर सतलुज नदी पर बना लोहे का पुल टूट गया है। साथ ही एक डंपर भी पुल सहित नदी में जा गिरा है। पुल के टूटने से सडक बंद हो गई। अब गाड़ियों को बाया उरनी-चोलिंग मार्ग से भेजा जा रहा है। डंपर में सवार व्यक्ति ठीक बताया जा रहा है। घटना के कारणों अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर घटना की जांच में लगी है। सभी वाहनों को बाया उरनी चोलिंग सडक मार्ग से भेजा जा रहा है।

समय से पूर्व यूरोप में पड रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कई इलाकों में हाई अलर्ट

- पेरिस। गर्मियों के मौसम की शुरूआत से पहले ही पश्चिमी यूरोप इस साल दूसरी बार एक भयानक हीटवेव की चपेट में आ गया है, जिससे इंग्लैंड से लेकर फ्रांस और जर्मनी तक के लोग एक साथ तपती गर्मी का सामना कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, और जून के महीने में इस तरह का तापमान देखकर हर कोई हैरान है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है, और फ्रांस में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, जहाँ तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। जर्मनी और इंग्लैंड में भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी पड़ रही है। इस खतरनाक मौसम के पीछे एक खास तरह का वैज्ञानिक कारण, जिसे हीट डोम कहा जाता है, काम कर रहा है। फ्रांस की मौसम एजेंसी ने अपने 60 विभागों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो उनका दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट है।21 जून से कुछ इलाकों में इसे रेड अलर्ट में भी बदला जा सकता है।

जब राष्ट्रपति ट्रंप को महसूस हुई भारत की ताकत, बदलने लगी भाषा

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरूआत से ही वैश्विक भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद, ट्रंप ने वैश्विक व्यापार पर अपना चिर-परिचित आक्रामक रुख दिखाया, अन्य देशों पर टैरिफ बम फोड़ते हुए उन्हें अपनी व्यापारिक शर्तों को मानने पर मजबूर करने का प्रयास किया। इस नीति ने विश्व स्तर पर काफी हलचल पैदा की, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ट्रंप के दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। 28 फरवरी तक ट्रंप लगातार देशों को भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दे रहे थे, जिससे वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव चरम पर था। हालांकि, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयानों और प्राथमिकताओं में नाटकीय बदलाव आया। ईरान के साथ हमलों में उलझने के बाद अमेरिकी सरकार का ध्यान व्यापारिक विवादों से पूरी तरह हटकर पश्चिम एशिया की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक साझेदारियों पर केंद्रित हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान ट्रंप ने न केवल टैरिफ को लेकर अपेक्षाकृत कम बयान दिए, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर भी पहले जैसी सक्रिय टिप्पणियां नहीं कीं।

बीते लगभग 100 दिनों का घटनाक्रम देखें, तो कई देशों ने अमेरिका से एक निश्चित दूरी बनाने की कोशिश की है। यूरोप के कुछ देशों ने सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई, जबकि पश्चिम एशिया के कई

देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। ऐसे माहौल में, अमेरिका के लिए भारत जैसे बड़े और विश्वसनीय साझेदार का महत्व और बढ़ गया। यही कारण है कि हाल के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना होने लगी। उन्होंने कई अवसरों पर मोदी को एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया। फ्रांस में जी7 बैठक के इतर पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात के बाद ट्रंप ने उन्हें एक बेहद मजबूत और महान नेता बताया, साथ ही तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने भारत को युद्धों से दूर रखा है, जो कि बेहद समझदारी भरा कदम है।

भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता है और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी नई दिल्ली की भूमिका अहम मानी जाती है। वाशिंगटन अब यह भली-भांति समझ चुका है कि एशिया-प्रशांत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धाक बचाए रखने के लिए उसे नई दिल्ली के सहयोग की सख्त जरूरत है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है, चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो या अमेरिका की शर्तों पर व्यापार समझौता करने से इनकार करना।

हालांकि, ट्रंप का झुकाव केवल भारत ही नहीं, बल्कि चीन की तरफ भी देखने को मिला है। उनका हालिया चीन दौरा और चीनी समकक्ष जिनपिंग की सराहना इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर टकराव से बचना चाहता है। व्यापारिक टकराव और कड़े बयानों के बावजूद, दोनों देश बातचीत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि चीन की तरफ से ट्रंप जैसा झुकाव अभी तक नहीं दिखा है। अब जब ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप अपने पुराने टैरिफ किंग वाले मिजाज में लौटते हैं और भारत सहित वैश्विक व्यापार पर उनका अगला कदम क्या होगा।

नासा का खास टेलीस्कोप पृथ्वी की ओर खिंच रहा, इसे बचाने जाएगा रोबोटिक यान

वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का स्विफ्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जो पिछले दो दशकों से ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों और रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, अब खतरे में है। साल 2004 में लॉन्च किया गया यह अंतरिक्ष दूरबीन धीरे-धीरे अपनी कक्षा खो रहा है और पृथ्वी की ओर खिंच रहा है। यदि समय रहते इसे बचाया नहीं गया तो यह साल 2026 के आखिर तक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलकर नष्ट हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरे को देखते हुए नासा ने ह्लस्विफ्ट बूस्ट मिशनह्व नामक एक विशेष बचाव अभियान शुरू किया है। इस मिशन के तहत एरिजोना स्थित कैटलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित ह्लिलंकह्व नामक अंतरिक्ष यान को स्विफ्ट तक भेजा जाएगा। यह यान स्विफ्ट के पास पहुंचकर उससे जुड़ेगा और उसे दोबारा ऊंची और सुरक्षित कक्षा में ले जाकर स्थापित करेगा। अंतरिक्ष इतिहास में किसी सक्रिय वैज्ञानिक वेधशाला को इस प्रकार बचाने का यह पहला प्रयास माना जा रहा है। स्विफ्ट को मूल रूप से केवल दो सालों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर 20 सालों तक काम किया। इस दौरान उसने 2000 से ज्यादा गामा-रे विस्फोटों और अन्य उच्च-ऊर्जा खगोलीय घटनाओं का पता लगाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी दूरबीन ने यह समझने में अहम भूमिका निभाई कि सोना, प्लैटिनम जैसे भारी तत्व ब्रह्मांडीय विस्फोटों के दौरान बनते हैं। स्विफ्ट की मौजूदा समस्या यह है कि उसमें स्वयं को ऊपर उठाने के लिए कोई प्रणोदन प्रणाली नहीं है। हाल के वर्षों में सूर्य की बढ़ी गतिविधियों के कारण पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल फैल गया है, जिससे स्विफ्ट पर अतिरिक्त घर्षण बल लग रहा है और उसकी कक्षा लगातार नीचे आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को प्रस्तावित लॉन्च के बाद लिंक अंतरिक्ष यान अपनी प्रणालियों का परीक्षण करेगा और फिर स्विफ्ट की ओर बढ़ेगा। सफल डॉकिंग के बाद वह कई महीनों तक धीरे-धीरे स्विफ्ट को उसकी पुरानी कक्षा तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। यदि मिशन सफल रहता है तो स्विफ्ट को कम से कम पांच साल का अतिरिक्त जीवन मिल सकता है।

सिंधु जल संधि पर पाक की गीदड़ भभकी, रक्षामंत्री बोले, जिस पल पानी पर खतरा लगा, हम जंग शुरू कर देंगे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी है। एक पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में

पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कमी लगातार बढ़ रही है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1 फीसदी पानी की कमी है। राइस कैनाल में 38 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। दादू कैनाल में 82 फीसदी तक पानी की कमी है। पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था के अहम हिस्से सुक्कुर बैराज को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।

हिमाचल के 37 दवा उद्योगों में बनीं 44 दवाएं जांच में फेल

हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह से लेकर गैस्ट्रिक रोगों की दवाओं के साथ चार सिरप भी शामिल, एक दवा निकली नकली

हिमाचल। देश की फार्मा हब के रूप में पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योगों पर एक बार फिर गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से जारी मई 2026 के ड्रग अलर्ट में प्रदेश के 37 दवा उद्योगों में निर्मित 44 दवाएं और चिकित्सा उत्पाद गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, संक्रमण, गैस्ट्रिक रोग, दर्द एवं सूजन जैसी आम और गंभीर बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इतना ही नहीं चार सिरप, चार मिसब्रांडेड उत्पाद तथा एक एंटीबायोटिक दवा को स्प्यूरियस (नकली) घोषित किया गया है। प्रदेश में निर्मित फेल दवाओं की संख्या देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। ड्रग अलर्ट के अनुसार देशभर में विभिन्न राज्यों में निर्मित कुल 157 दवा एवं चिकित्सा उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें 111 उत्पाद राज्य स्तरीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और 46 उत्पाद सीडीएससीओ की केंद्रीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की जांच में सब-स्टैंडर्ड पाए गए। हिमाचल प्रदेश में निर्मित 44 उत्पाद भी इसी सूची में शामिल हैं।

ये उत्पाद बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, झाड़माजरी, कालाअंब, पांवटा साहिब, परवाणू और ऊना स्थित दवा उद्योगों में तैयार किए गए थे। जांच में फेल हुई दवाओं में आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, रेबेप्राजोल इंजेक्शन, डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन, ओन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, एमोक्सिसिलिन एवं क्लैवुलैनिक एसिड टैबलेट, सेफिक्सिम टैबलेट, सेफपोडॉक्सिम टैबलेट, टेल्मीसार्टन टैबलेट, रोसुवास्टेटिन टैबलेट,

एटोरवास्टेटिन टैबलेट, गैबापेंटिन टैबलेट, प्रेगाबालिन टैबलेट, लेवोसिटिरिजीन टैबलेट, ओमेप्राजोल एवं इट्राकोनाजोल कैप्सूल, खांसी की विभिन्न सिरप, विटामिन सप्लीमेंट तथा मधुमेह और उच्च रक्तचाप की कई दवाएं शामिल हैं। इंजेक्शन और सिरप श्रेणी के उत्पादों में गुणवत्ता संबंधी खामियां नियामक एजेंसियों के लिए अधिक संवेदनशील मानी जाती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव सीधे मरीजों के उपचार पर पड़ सकता है।

रोजाना इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल

गुणवत्ता जांच में फेल हुई दवाओं में बड़ी संख्या ऐसी दवाओं की है, जिनका इस्तेमाल लाखों मरीज नियमित रूप से करते हैं। उच्च रक्तचाप की टेल्मीसार्टन, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने वाली रोसुवास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन, गैस्ट्रिक रोगों के लिए रेबेप्राजोल और ओमेप्राजोल, मधुमेह की दवाएं, एंटीबायोटिक श्रेणी की एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलैनिक एसिड, सेफिक्सिम और सेफपोडॉक्सिम जैसी दवाओं का सूची में शामिल होना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। ड्रग अलर्ट में सबसे गंभीर मामला एक एंटीबायोटिक दवा का सामने आया है, जिसे स्प्यूरियस (नकली) घोषित किया गया है। यह उत्पाद सिरमौर स्थित एक कंपनी के नाम से बाजार में पाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेल केवल संबंधित बैच होते हैं, पूरी दवा या ब्रांड नहीं। राज्य दवा नियंत्रक डा. मनीष कपूर ने बताया कि गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए उत्पादों से संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संबंधित बैचों को बाजार से वापस लेने (रिकॉल) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा मामलों की विस्तृत जांच की जा रही है। मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा।

दिल्ली में मुगलकाल की ऐतिहासिक इमारतों में से लालकिला से हो रही लाखों की कमाई

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो मुगलकाल की बहुत सारी ऐतिहासिक इमारते और स्मारक हैं लेकिन उनमें लालकिला एक स्मारक ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। मुगल काल की इस भव्य धरोहर को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक देश और विदेश से यहां आते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह से लेकर इसकी शानदार वास्तुकला तक, लालकिला भारतीय इतिहास और संस्कृति का अहम प्रतीक है। यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लालकिले ने टिकट बिक्री से लगभग 18.09 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। इस अवधि में करीब 28.78 लाख पर्यटकों ने लालकिला देखा। यदि इस आय को पूरे साल के दिनों में बांटा किया जाए तो औसतन प्रतिदिन करीब 4.95 लाख रुपए की कमाई केवल टिकटों की बिक्री से होती है। पर्यटन के व्यस्त मौसम, विशेष छुट्टियों और त्योहारों में यह राशि और ज्यादा बढ़कर छह से आठ लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। लालकिले में भारतीय नागरिकों और सार्क और बिम्सटेक देशों के पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 35 रुपए तय है, जबकि विदेशी पर्यटकों को 500 से 550 रुपए तक का टिकट खरीदना पड़ता है। इसके अलावा वीडियो कैमरा ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाता है। 15 साल से कम आयु के बच्चों को प्रवेश के लिए कोई टिकट नहीं लेना पड़ता।

विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी पर्यटकों से मिलने वाला राजस्व लालकिले की कुल आय में अहम योगदान देता है, क्योंकि उनकी टिकट दर भारतीय पर्यटकों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। लालकिले से मिलने वाला पूरा टिकट राजस्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जाता है। यह संस्था देशभर के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, मरम्मत, सुरक्षा और रखरखाव का कार्य करती है। लालकिले जैसे विशाल और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक की देखभाल पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, उद्यानों का रखरखाव, प्रकाश व्यवस्था, सफाई, तकनीकी सुविधाएं और संरक्षण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा लालकिले से होने वाली आय का इस्तेमाल उन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में भी किया जाता है, जहां पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकट बिक्री के अलावा लालकिले को अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त होती है।

लाइट एंड साउंड शो, परिसर में संचालित दुकानों और कैफे का किराया, पार्किंग शुल्क और अन्य सुविधाओं से भी राजस्व अर्जित होता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल लालकिला दिल्ली पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है। विशेषज्ञों के मुताबिक लालकिले से होने वाली कमाई केवल आर्थिक दृष्टि से अहम नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाती है।

स्पेन के पीएम की पत्न ी के विदेश जाने पर रोक, पासपोर्ट जब्त

मैड्रिड। स्पेन के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए उनका पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया गया। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के आरोपों के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए हर दो हफ्ते में न्यायालय में हाजिरी लगाने का भी निर्देश दिया है। जांच कर रहे न्यायाधीश ने गोमेज के देश छोड़कर जाने की आशंका जताई है, जिसके चलते यह कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

चीन ने डीएफ-17 का वीडियो जारी कर दुनिया को चौंकाया

बीजिंग,(ईएमएस)। काले घने बादलों को चीरती हुई एक गड़गड़ाहट और अगले ही पल गोबी मरुस्थल की रेतीली जमीन को झकझोरता हुआ एक आसमानी बवंडर, यह दृश्य उस खौफनाक वीडियो का हिस्सा है जिसे चीनी सेना ने अपनी सबसे गुप्त और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल डोंगफेंग-17 (डीएफ-17) के सफल लॉन्च के बाद दुनिया के सामने जारी किया है। इतिहास में पहली बार बीजिंग ने इस अदृश्य ब्रह्मास्त्र के लाइव महाविनाश का वीडियो जारी कर बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज भागने वाली यह मिसाइल पहले अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों में जाती है और फिर वहां से लौटकर सांप की तरह रास्ता बदलते हुए दुश्मन पर ऐसा अचूक वार करती है कि दुनिया के बड़े से बड़े रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने प्रभावहीन सिद्ध होने लगते हैं। ड्रैगन की इस लाइव दहाड़ ने साफ कर दिया है कि अब प्रशांत महासागर में अमेरिकी जंगी जहाजों और ताइवान की खैर नहीं।

डीएफ-17 को रक्षा विशेषज्ञ गेम चेंजर और कैरियर किलर कहते हैं क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत प्रशांत महासागर में तैरने वाले उसके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन डीएफ-17 इतनी तेज रफ्तार और अचूक सटीकता से आती है कि यह चलते हुए अमेरिकी युद्धपोतों को समुद्र में डुबो सकती है। इस वीडियो को जारी कर चीन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि यदि उसने ताइवान या दक्षिण चीन सागर के विवाद में पैर अड़ाया तो उसके अरबों डॉलर के एयर डिफेंस और नेवी शिप सुरक्षित नहीं रहेंगे, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने का संकेत है। चीनी सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने अपने सबसे घातक हथियारों में से एक डोंगफेंग-17 (डीएफ-17) हाइपरसोनिक मिसाइल के लाइव लॉन्च का यह वीडियो जारी किया है। गोबी मरुस्थल में चीनी रॉकेट फोर्स के युद्धाभ्यास के दौरान हुआ यह लाइव लॉन्च सीधे तौर पर अमेरिकी गुट और फर्स्ट आइलैंड चेन (ताइवान, जापान, फिलीपींस) के लिए बीजिंग की ओर से एक खुली कूटनीतिक और सैन्य चेतावनी है।

द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस को मिला प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय पुरस्कार

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित 350 वर्ष पुराना द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय पुरस्कार कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2026 के दुनिया के सबसे खूबसूरत होटलों की सूची में शामिल किया गया है। यह राजमहल लगभग 350 वर्ष पुराना है और इसे बुंदेला वंश के महाराजा हिंदू पत द्वारा निर्मित कराया गया था।

बुंदेलखंड की पारंपरिक वास्तुकला का यह उत्कृष्ट उदाहरण अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य लग्जरी होटल के रूप में विकसित किया गया है। प्राचीन शाही भव्यता और आधुनिक आराम का संतुलित संगम इसे विशेष बनाता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। प्रिक्स वर्साय ने अपनी टिप्पणी में इस संपत्ति की राजसी भव्यता की सराहना करते हुए इसे

भारतीय आतिथ्य के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बताया है। दुनिया भर से चुनी गई केवल 16 संपत्तियों को इस सूची में स्थान मिला है, जो इस महल की विशिष्टता को और बढ़ाता है।

द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट मनियागढ़ पहाड़ियों के बीच स्थित है। घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह परिसर पहले एक किले के रूप में इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में एक आलीशान विरासत होटल में परिवर्तित किया गया। यहां आने वाले पर्यटकों को इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। होटल के भीतर शाही साज-सज्जा, विशाल आंगन, पारंपरिक कलाकृतियां और शानदार भोजन व्यवस्था मेहमानों को राजसी अनुभव प्रदान करती हैं। यहां एक रात रुकने का खर्च लगभग 40 हजार रुपये से शुरू होता है, जबकि सबसे आलीशान सुइट्स की कीमत 11 लाख रुपये प्रति रात से अधिक बताई गई है। इस वर्ष प्रिक्स वर्साय की सूची में भारत को केवल होटल श्रेणी में ही नहीं, बल्कि रेस्तरां श्रेणी में भी सम्मान मिला है।

...महत्वपूर्ण होती जा रही है

पुणे स्थित रोसो रेस्तरां को दुनिया के सबसे खूबसूरत रेस्तरां की सूची में शामिल किया गया है। यह रेस्तरां होटल इरादा परिसर में स्थित है और अपनी भूमध्यसागरीय शैली की सजावट तथा आधुनिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। रोसो में परोसे जाने वाले इटैलियन व्यंजनों के साथ-साथ इसकी आकर्षक आंतरिक सज्जा, गर्मजोशी भरा वातावरण और कलात्मक प्रस्तुति ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। पर्यटन उद्योग में अब केवल आरामदायक ठहराव या स्वादिष्ट भोजन ही पर्याप्त नहीं माना जाता। यात्री ऐसे अनुभवों की तलाश में हैं जो संस्कृति, इतिहास, डिजाइन और स्थानीय पहचान से जुड़ाव महसूस कराएं। प्रिक्स वर्साय जैसे पुरस्कार इस बात को रेखांकित करते हैं कि आतिथ्य उद्योग में वास्तुकला और डिजाइन की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।

जहां कभी आतंक और भय का माहौल था, वहां आज विकास, विश्वास और अवसरों का नया दौर : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेशन फर्स्ट संकल्प और सुरक्षा बलों के शौर्य से बस्तर में लौटी शांति और विकास की नई रोशनी - मुख्यमंत्री

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को विकास और जनविश्वास की विजय बताते हुए कहा है कि सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया था और आज उसके सकारात्मक परिणाम पूरे देश के सामने हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय, हिंसा और अविश्वास का वातावरण था, वहां आज विकास, सुशासन और नई संभावनाओं का युग प्रारंभ हो चुका है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य नागरिक निरंतर भय के साये में जीवन जीने को मजबूर थे। लोगों को अपनी सुरक्षा, आजीविका और सम्मान की चिंता रहती थी। विकास कार्यों को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन था। सड़क निर्माण से लेकर संचार सुविधाओं के विस्तार तक हर प्रयास का हिंसक विरोध किया जाता था। कई बार निर्माण सामग्री को जला दिया जाता था, ठेकेदारों को धमकाकर भगा दिया जाता था और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की जाती थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बीते वर्षों में हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, हजारों मोबाइल टावर स्थापित किए गए और दूरस्थ गांवों तक संचार सुविधाएं पहुंचाई गईं। बैंकिंग सेवाओं, डाक सेवाओं और वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में विश्वास और अवसरों का विस्तार है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल बम, बंदूक और गोली के सहारे नहीं लड़ी गई। सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ जनसामान्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने पर भी समान रूप से ध्यान दिया। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, गरीबों को अधिकार दिलाने और लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत करने के निरंतर प्रयास किए गए। इसी का परिणाम है कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आमजन का भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास की प्रक्रिया में बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने बस्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां कभी आतंक और हिंसा का माहौल था, वहां आज युवाओं की ऊर्जा खेल और प्रतिभा के माध्यम से सामने आ रही है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में लाखों युवाओं की भागीदारी इस परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। यह दर्शाता है कि अब वहां के युवा हिंसा के रास्ते को नहीं, बल्कि अवसर, शिक्षा, खेल और विकास के मार्ग को अपना रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ह्यनेशन फर्स्टह्व संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस ने बस्तर सहित पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कभी नक्सलवाद का आतंक था, वहां आज विकास का आत्मविश्वास दिखाई देता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच ने लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षा बलों की वीरता तथा स्थानीय जनता के सहयोग से नक्सलवाद का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की पहचान हिंसा नहीं, बल्कि विकास, जनभागीदारी, खेल, पर्यटन और नई संभावनाओं से बन रही है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और अंत्योदय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

ताजा खबर

संक्षिप्त

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सशक्त प्रहरी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद्,भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। उनके विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र एवं राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं।

युवती की संदिग्ध मौत के बाद 100 ठिकानों पर छापेमारी, 200 जवानों ने की जांच

राजनांदगांव. राजनांदगांव पुलिस ने सोमनी थाना क्षेत्र के मनगटा स्थित विभिन्न रिसॉर्ट में दबिश दी। यह अभियान असामाजिक गतिविधियों और अन्य अवैध चीजों की जांच के लिए चलाया गया। मनगटा के एक रिसॉर्ट में युवती की संदिग्ध मौत के बाद यह कार्रवाई की गई। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस दल ने एडिशनल पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के नेतृत्व में दबिश दी। नगर पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी भी इस अभियान में शामिल थे। लगभग 200 पुलिस बल ने लगभग 100 रिसॉर्ट की गहनता से जांच की। इस दौरान असामाजिक गतिविधियों और अवैध शराब की पड़ताल की गई। पुलिस ने रिसॉर्ट संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एडिशनल पुलिस अधीक्षक राठौर ने अवैध मादक पदार्थों के सेवन पर चिंता जताई। उन्होंने लोगों को रिसॉर्ट में गलत तरीके से ठहराने की भी जांच की बात कही। यह अभियान असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा है। पुलिस ने 15 थाना प्रभारियों के साथ मिलकर रिसॉर्ट में समझाइश दी। एडिशनल पुलिस अधीक्षक राठौर ने बताया कि यह जांच लगातार जारी रहेगी। इसका लक्ष्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री साय करेंगे 2036 पौधों के वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर 23 जून को छत्तीसगढ़ में खेल और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीएसएफ कैंप, नया रायपुर स्थित ग्राम पलौद में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे होगा। मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति से खिलाड़ियों, खेल संगठनों तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ेगा।

महासमुंद के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरों की प्राप्ति से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगा नया आयाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरों की प्राप्ति ने प्रदेश को खनिज संपदा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण एवं प्रसंस्करण के बाद कुल 5 हीरे प्राप्त हुए हैं, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 333 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

राजनांदगांव को 510 करोड़ लागत की विकास कार्यों की सौगात

खरीफ 2026 से दलहन-तिलहन और अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजना की घोषणा, सुशासन और ग्रामीण विकास पर दिया जोर।

रायपुर। किसानों की समृद्धि, गांवों का विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में विकास और सुशासन के नए अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले को 510 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक की लागत के 333 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शिवनाथ नदी के मोहारा मेला स्थल से ऑक्सीजन जोन तक सस्पेंशन ब्रिज, ईरा एनीकट निर्माण एवं संरक्षण कार्य, कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग निर्माण तथा घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले ने फसल चक्र परिवर्तन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। यहां किसानों को पारंपरिक खेती के साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन अथवा अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और अन्य किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को खेती के लिए आवश्यक खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुशासन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने सीएम हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की है, जहां नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कराकर निर्धारित समय-सीमा में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के माध्यम से आय, जाति, निवास सहित विभिन्न विभागों की 400 से अधिक सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं।

रेलवे बोर्ड में डीजी हितेंद्र मल्होत्रा ने किया रायपुर रेल मंडल का सेफ्टी निरीक्षण

रायपुर। रेलवे बोर्ड के महानिदेशक संरक्षा हितेंद्र मल्होत्रा ने दपूमरे रायपुर रेल मंडल में आज सेफ्टी निरीक्षण किया गया। श्री मल्होत्रा ने कोचिंग डिपो दुर्ग में यात्री गाड़ियों की मेंटेनेंस व्यवस्थाओं के सेफ्टी पहलुओं का निरीक्षण किया। कोचिंग डिपो दुर्ग में ट्रेनों के शंटिंग की सावधानियां, फायर डिटेक्शन सिस्टम, की सभी प्रमुख लाइन स्टाफ को जानकारी । विभागीय संसाधनों से निर्मित फीबा टेस्ट स्टैंड जो ट्रेन के पार्ट्स की जांच करती है। फायर डिटेक्शन सिस्टम मॉडल की कार्यविधि, ट्रेन के कोचों की इंटरमीडिएट ओवरहालिंग शॉप शेड्यूल की जांच की।

दुर्ग लॉबी में लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर के ट्रेन परिचालन के संरक्षा नियमों पर चर्चा कर लॉबी की व्यवस्थाओं को देखा एवं क्रू मेंबर्स के प्रशिक्षण पर जोर दिया । डीएम ग्रिड भिलाई में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ((एआरटी) एवं एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन (एआरएमवी) एवं हैवी क्रेन के कार्य प्रणाली के डेमो का निरीक्षण यात्री कोच एंड वैगन के व्हील सेट के उपयोग में आने वाली व्हील स्केट ट्रॉली टोइंग मशीन का शुभारंभ किया।

भिलाई में इंजीनियरिंग स्टोर का निरीक्षण कर स्क्रैप के डिस्पोजल पर जोर दिया तथा यांत्रिक उपयोग में आने वाले सभी सभी पार्ट्स, स्प्रिंग, पुर्जे सामान को संरक्षा गुणवत्ता जांच के पश्चात ही उपयोग करने निर्देशित किया। इसके बाद मल्होत्रा ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में संरक्षा संबंधित कार्यों कि समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीआरएम दयानंद, बिलासपुर जोन के प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी अनूप कुमार सतपथी, समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएसआईडीसी संचालक मंडल की बैठक सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) की 161वीं संचालक मंडल बैठक आज सोमवार को रायपुर स्थित उद्योग भवन में अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रमुख रूप से देवेन्द्र नगर (पंडरी), रायपुर में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना हेतु आगे की कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य में टेक्सटाइल पार्क एवं रेडीमेड गारमेंट पार्क में निवेश आकर्षित करने तथा संबंधित प्रक्रियाओं को तेज करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी श्री विश्वेश कुमार, संचालक उद्योग संचालनालय श्री प्रभात मलिक, संयुक्त सचिव वित्त विभाग श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी तथा अपर संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री संदीप बागड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बलौदाबाजार में 6 क्रशर सील, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अवैध रेत खनन में लगी चेन माउंटेड जब्त

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। शासन की मंशा खनिज संसाधनों के संरक्षण, उनके नियमानुसार उपयोग तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश सुनिश्चित करने की है।

इसी कड़ी में खनिज साधन के विभाग के सचिव और संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनि उडन्दस्ता की संयुक्त टीम ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर 21 एवं 22 जून को विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान जिला बलौदाबाजार के ग्राम खपरीडीह में गौण खनिज निम्न श्रेणी चूनापत्थर से संबंधित स्वीकृत अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति स्थलों एवं खदानों का निरीक्षण किया गया। जांच में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर 06 क्रशर इकाइयों को सीलबंद किया गया तथा संबंधित संचालकों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम दहिदा में महानदी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक चैन माउंटेन मशीन द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना पाया गया। खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त मशीन को जब्त कर आगामी आदेश तक सीलबंद किया गया। मशीन को मशीन ऑपरेटर की सुपुर्दगी में दिया गया है तथा मशीन स्वामी को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त सभी स्थलों की जांच एवं सत्यापन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से भी किया गया, जिससे खनन गतिविधियों का सटीक आकलन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा खनिज संपदा के नियमानुसार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

खनिज सचिव पी. दयानंद ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आधुनिक तकनीक, ड्रोन सर्वेक्षण एवं सतत निगरानी के माध्यम से अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस कार्रवाई में केंद्रीय उडन्दस्ता की संयुक्त जांच टीम एवं संबंधित जिलों की जिला स्तरीय टीम के अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में 12 तहसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर, सरकार ने जारी किए पदोन्नति और पदस्थापना आदेश

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 तहसीलदारों को पदोन्नति देकर डिप्टी कलेक्टर बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया है। प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में नई जिम्मेदारी दी गई है।सरकार ने जिन तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाया है, उनमें रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, बालोद समेत कई जिलों में पदस्थ अधिकारी शामिल हैं। आदेश के मुताबिक, अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (?56,100-1,77,500) में डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है। प्रमोशन के बाद किसे कहां मिली जिम्मेदारी अधिकारी का नाम पहले पदस्थापना नई जिम्मेदारी भवानी शंकर साव तहसीलदार, महासमुंद डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर मुकेश कुमार बजाज तहसीलदार, आयुक्त भू-अभिलेख नवा रायपुर डिप्टी कलेक्टर, धमतरी सालिक राम गुप्ता तहसीलदार, रामानुजगंज (बलरामपुर) डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर कृष्ण कुमार साहू तहसीलदार, महासमुंद डिप्टी कलेक्टर, बेमेतरा, रिचा सिंह तहसीलदार, रायगढ़ डिप्टी कलेक्टर, जांजगीर-चांपा शिल्पा भगत तहसीलदार, बिलासपुर डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ राकेश कुमार वर्मा राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ प्रेमूलाल साहू तहसीलदार, धमतरी डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग प्रकाश सोनी तहसीलदार, रायपुर डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग आशुतोष शर्मा तहसीलदार, बालोद डिप्टी कलेक्टर, कबीरधाम अभिषेक राठौर तहसीलदार, बिलासपुर डिप्टी कलेक्टर, कोरबा मीना साहू तहसीलदार, दुर्ग डिप्टी कलेक्टर, रायपुर

1986 में निजी जमीन पर बनाई गई थी सड़क, मुआवजे के लिए भूमि मालिकों ने 40 वर्षों तक लड़ी कानूनी लड़ाई; सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

निजी जमीन पर सड़क बनाकर 40 साल तक नहीं दिया मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगाई फटकार

वर्ष 1986 में बिना अनुमति बना दी गई थी सड़क

कब्जे के 24 साल बाद शुरू हुई अधिग्रहण प्रक्रिया

नई दिल्ली। निजी जमीन पर बिना अनुमति सड़क निर्माण कर दशकों तक मुआवजा नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि आठ सप्ताह के भीतर प्रभावित भूमि मालिकों को देने का निर्देश दिया। करीब 40 वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष करने के बाद भूमि मालिकों को आखिरकार राहत मिली। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने निजी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा किया और लंबे समय तक उसका उपयोग करने के बावजूद उचित मुआवजा नहीं दिया। जून 2011 में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अंतिम अवॉर्ड जारी करते हुए जमीन का मूल्य 4,308 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया। हालांकि भूमि मालिकों ने इस मूल्यांकन को अपर्याप्त बताते हुए चुनौती दी।

1986 में बिना अनुमति बना दी गई सड़क

मामले की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई, जब लोक निर्माण विभाग (क्कङ्ख्रष्ठ) ने एक निजी भूमि पर सड़क का निर्माण कर दिया। आरोप है कि जमीन मालिकों से न तो अनुमति ली गई और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। बाद में सीमांकन प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सड़क निजी भूमि पर बनाई गई है। इसके बाद भूमि मालिकों ने वर्ष 2006 में अदालत का रुख करते हुए विभाग को जमीन से हटाने और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की।

कब्जे के 24 साल बाद शुरू हुई अधिग्रहण प्रक्रिया

भूमि मालिकों द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। यानी जिस जमीन पर 1986 में सड़क बनाई गई थी, उसके लिए अधिग्रहण की कार्रवाई लगभग 24 साल बाद की गई।

मुआवजा बढ़ा, ब्याज देने का भी आदेश

मामला रेफरेंस कोर्ट पहुंचा, जहां मुआवजे की दर बढ़ाकर 5,380 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गई। इसके बाद दोनों पक्ष छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने रेफरेंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को वर्ष 2006 से ब्याज देने का निर्देश दिया। अदालत ने पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद भुगतान होने तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलें खारिज कीं

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि राज्य ने भूमि मालिकों की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा किया और वर्षों तक उसका उपयोग करता रहा। इसके बावजूद प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में हाई कोर्ट द्वारा ब्याज देने का आदेश पूरी तरह न्यायोचित है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य सरकार की अपील से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले से पीड़ित भूमि मालिकों को और अधिक मुकदमेबाजी में उलझाना चाहती है, जबकि निचली अदालतों के निष्कर्ष तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सही हैं।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 30 अधिकारियों के तबादले, रायपुर-दुर्ग समेत कई जिलों के अफसर बदले

सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को पूरी तरह निराधार बताते हुए उस पर 2 लाख रुपये की लागत (कॉस्ट) लगाई। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि आठ सप्ताह के भीतर भूमि मालिकों को भुगतान की जाए। इस फैसले को निजी संपत्ति के अधिकार और भूमि मालिकों को समय पर उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

मिताली का सुझावः हरमनप्रीत नंबर चार पर, जेमिमा नंबर पांच पर खेलें

मैनचेस्टर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने टीम के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव का सुझाव दिया है। मिताली का मानना है कि कप्तान हरमनप्रीत कौर को नंबर चार पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स को नंबर पांच पर उतारा जाना चाहिए। मिताली ने ये बात दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार को देखते हुए कही है। इससे सेमीफाइनल में पहुंचने की भारतीय टीम की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें अपने शेष सभी मैच जीतने होंगे।

मिताली ने कहा कि अब भारतीय टीक को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मैच भारत के जीतने लायक था, लेकिन अब आगे का रास्ता मुश्किल है। बल्लेबाजी क्रम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, हमने हरमनप्रीत को नंबर 5 पर इतनी देर से बल्लेबाजी करते हुए बहुत कम देखा है। इसलिए, शायद वह नंबर चार पर और जेमिमा नंबर पांच पर आ सकती हैं।

उन्होंने जेमिमा को नंबर पांच पर भेजने को लेकर कहा, जेमिमा पहले भी नंबर पांच पर खेल चुकी हैं और वहां उन्होंने काफी रन बनाए हैं। जब वह बल्लेबाजी के लिए आएंगी, तो संभावना है कि उन्हें स्पिनरों का सामना करना पड़े, जो उनकी ताकत है। वह अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकती हैं और स्कूप और स्वीप शॉट अच्छे से खेलती हैं। मिताली का मानना है कि इस बदलाव से जेमिमा का आत्मविश्वास बढ़ सकता है, वह लय में वापस आ सकती हैं और वह मोमेंटम दोबारा हासिल कर सकती हैं, खासकर अगर हरमनप्रीत उनसे पहले बल्लेबाजी करें।

मिताली ने बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरानी की अनुशासित गेंदबाजी को इस मैच में भारत के लिए सबसे सकारात्मक पहलू बताया। चरानी ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को दबाव में ला दिय था। और बाद में एक और महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर अपना शानदार स्पेल समाप्त किया। पूर्व कप्तान ने चरानी की तारीफ करते हुए कहा, श्री चरानी जल्दी सीखने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने इंग्लिश कंडीशंस में डेब्यू किया था, इसलिए उन्हें वहां के हालात की अच्छी जानकारी है। उन्होंने बताया कि पिच से ज्यादा टर्न न मिलने के बावजूद, चरानी ने लगातार स्टंप्स पर अटैक किया, पेस और लेंथ में बदलाव किए, और अपनी पसंद के हिसाब से फील्ड सेट की। चरानी के दो बड़े विकेट ने भारत को खेल में वापस ला दिया था, और दूसरे स्पेल में भी उनकी लाइन बहुत सटीक थी।

वाइल्ड कार्ड के जरिये विंबलडन में वापसी करेंगी सेरेना : ऑल इंग्लैंड क्लब

लंदन। अमेरिका की अनुभीव महिला टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स 44 साल की उम्र में विंबलडन टेनिस टूनामेंट में वापसी करने जा रही हैं। इसके लिए उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिये प्रवेश दिया गया है। सेरेना ने साल 2022 में खेल से संन्यास ले लिया था। वहीं अब वह चार साल खेल से दूर रहने के बाद फिर से कोर्ट में नजर आयेंगी। पिछले कुछ दिनों से उनकी वापसी की अटकलें थी जो अब सही साबित हुई हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब ने अपने एक बयान में सब कुछ साफ कर दिया है सेरेना 29 जून से शुरू हो रहे विंबलडन में खेलेंगी। ऑल इंग्लैंड क्लब ने अपने एक बयान में कहा, सेरेना को महिला एकल वर्ग में अंतिम वाइल्ड कार्ड दिया गया है। सेरेना इस तरह से विंबलडन में एकल और युगल दोनों ही वर्ग में खेलेंगी। उन्होंने पहले ही अपनी बड़ी बहन वीनस के साथ युगल प्रतियोगिता के लिए वाइल्ड कार्ड हासिल कर लिया है।

डब्ल्यूटीए टूर ने कहा, विंबलडन ने महिला एकल वर्ग में आठवें और अंतिम वाइल्ड कार्ड को सेरेना के लिए बचाये रखा था। इसी सप्ताह की शुरूआत में बर्लिन में युगल मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह इस फैसले को लेकर दुविधा में हैं। सेरेना ने अंतिम समय तक अपने खेलने को लेकर संशय बनाए रखा था, क्योंकि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या वह एकल मुकाबले में वापसी करेंगी तो उन्होंने जवाब दिया था, क्या आपको लगता है कि मैं एकल मुकाबले के लिए तैयार हूं.

गौरतब है कि अपने करियर में सेरेना ने एकल में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. इनमें से सात विंबलडन खिताब शामिल हैं। उन्होंने 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 और 2016 में विंबलडन खिताब जीता है। उन्होंने युगल में भी वीनस के साथ 14 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनमें से छह विंबलडन में जीते हैं। सेरेना ने 2012 के लंदन ओलंपिक में एकल और युगल में वीनस के साथ दोनों खिताब जीते थे, जब टेनिस प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड क्लब में खेली गई थी।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, जेम्स कोल्स की एंट्री

लंदन। इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक की कप्तानी में एक जुलाई से भारत के खिलाफ शुरू होने टी-20 सीरीज के लिए जेम्स कोल्स को टीम में बुलाया है। इंग्लैंड ने सोमवार दोपहर पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों की बड़ी टीम का ऐलान किया। इसमें ससेक्स के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार बुलावा मिला है। लेकिन शेष टीम वैसी ही है जिसने टी-20 विश्व कप में हिस्सा लिया था। उस दौरान इंग्लैंड को सेमीफाइनल में भारतीय टीम से हार मिली थी। विश्व कप में औसत प्रदर्शन के बावजूद जॉस बटलर टीम में बने हुए हैं, जबकि 36 साल के लियम डॉसन की वापसी भी अहम है।

वैभव सूर्यवंशी ने पहनी टीम इंडिया की जर्सी, आंखों में थे आंसू और जुबां पर आई दिल की बात

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की टीम में चुना गया है। सोमवार 22 जून को उन्हें टीम इंडिया की जर्सी भी मिल गई है, जिस पर 3 स्टार बने हुए हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने तीन टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वैभव उस जर्सी को पहने नजर आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इस पल को बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की नई किट मिल चुकी है। इसका वीडियो बीसीसीआई ने एक्स पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, शब्द नहीं हैं इस चीज को व्यक्त करने के लिए। जिस चीज के लिए मैंने पहले दिन बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पर मैं गया, प्रैक्टिस के लिए, वह ड्रीम आज मेरा पूरा हुआ। जो मैन स्टेप होता है, वह आज कंप्लीट हो गया। मैं इस चीज को शब्दों में बयां नहीं कर सकता।

वैभव सूर्यवंशी को जर्सी और उनकी किट से भरा हुआ बॉक्स रघु ने दिया था। दोनों ने एकदूसरे को राम-राम बोला। इस दौरान वैभव ने रघु के पैर भी छूए। वहीं, जर्सी पाने के बाद उन्होंने कहा, वह एक सपने जैसा लग रहा था। जैसे ही मैंने टी शर्ट देखी तो मैं इतना खुश हो गया कि क्या बताऊं। कभी-कभी होता है कि जो चीज आप सोचते नहीं और वह हो जाती है तो आप रिएक्ट नहीं कर पाते। यही चीज मेरे साथ हुई। आपको बता दें, 21 जून तक वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका में इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन वनडे सीरीज खेल रहे थे। अगले दिन वह भारत आए और फिर थोड़ा बहुत आराम करने के बाद यूके के टूर के लिए निकल गए, जहां टीम इंडिया को 26 जून को पहला टी20 इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, जबकि 28 जून को दूसरा टी20 मैच दोनों के बीच खेला जाएगा। एक जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो जाएगी।

वैभव बना सकते हैं रिकॉर्ड

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अगर आयरलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वह देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है। आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने का इनाम उनको मिला था। आईपीएल में वैभव ने पांच बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए थे। ऑरेंज कैप से लेकर इमर्जिंग प्लेयर तक का अवॉर्ड उन्होंने जीता था।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे अधिक बार शून्य पर आउट हुए सचिन

मुम्बई। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई रिकार्ड है। सचिन ने सभी टीमों के खिलाफ जमकर रन बनाये हैं। उनके बल्ले से किसी गेंदबाज का बचना असंभव रहा है। इसके बाद भी कई बार ऐसा भी हुआ है जब सचिन खाता नहीं खोल पाये हों। हैरान की बात ये है कि वह सबसे अधिक उन्हें शून्य पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने आउट किया है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो सचिन अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे अधिक बार वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 बार शून्य पर आउट हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 7 बार और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 बार बिना वह शून्य पर आउट हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वह 5 बार खाता नहीं खोल पाये थे। वहीं कुछ टीमें ऐसी भी रहीं जिनके गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन को कभी शून्य पर आउट नहीं कर पाए। इनमें बांग्लादेश 19 मैच, बरमूडा 1 मैच, इंग्लैंड 19 मैच, आयरलैंड 2 मैच, केन्या 10 मैच, नामिबिया 1 मैच, नीदरलैंड 2 मैच, यूएई 2 मैच शामिल हैं। सचिन ने अपने 24 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले.

इसमें वह तीनो प्रारुपों को मिला दिया जाये तो कुल 34 बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए हैं। सचिन के करियर के ओवरऑल रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो वे टेस्ट मैचों की तुलना में एकदिवसीय क्रिकेट में ज्यादा बार जीरो पर आउट हुए हैं। कुल 34 बार डक का शिकार हुए सचिन एकदिवसीय क्रिकेट में 20 बार 0 पर आउट हुए, जबकि टेस्ट क्रिकेट में यह संख्या 14 रही।

सैमसन ने धोनी की तुलना फेडरर और विराट की अल्कारेज से की

मुम्बई। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर आजकल विंबलडन टेनिस का रंग चढ़ा हुआ है। इसी को देखते हुए सैमसन ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना स्विटजरलैंड के महान टेनिस स्टार रोजर फेडरर से की है। सैमसन ने जहां धोनी की तुलना टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर से जबकि विराट कोहली के आक्रामक अंदाज की तुलना स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से की है।

सैमसन ने कहा, क्रिकेट के रोजर फेडरर धोनी ही हो सकते हैं। जिस प्रकार से फेडरर शांत अंदाज में खेलते हैं। उसी प्रकार से धोनी भी अपने काम को बहुत शांत और संयमित तरीके से करते हैं। वहीं दूसरी ओर अल्कारेज बहुत आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। जिस प्राकर से विराट कोहली खेलते हैं। इसलिए संजू ने विराट की तुलना अल्कारेज से की है। सैमसन टी20 विश्वकप में भारतीय टीम की जीत के बाद से ही छाये हुए हैं। उन्होंने इसके बाद आईपीएल में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब उनकी नजरें इंग्लैंड दौरे पर हैं। सैमसन ने टी20 महिला विश्वकप में भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महिला टीम ने एकदिवसीय विश्वकप जीता उसी प्रकार वह टी20 खिताब भी जीतेगी।

25 जून के बाद बढ़ सकती है परेशानी! जानिए कब-कब बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली। अगर इस सप्ताह आपको बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम करना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नकदी निकालना, चेक जमा करना, डिमांड ड्रॉफ्ट बनवाना या किसी अन्य बैंक शाखा से संबंधित काम को टालना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में देश के कई हिस्सों में बैंक लगातार तीन दिनों तक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने सभी जरूरी बैंकिंग काम पहले ही पूरा कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

हालांकि, राहत की बात यह है कि 22 जून से 25 जून तक बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इन दिनों सरकारी और निजी दोनों बैंक अपनी नियमित सेवाएं देते रहेंगे और ग्राहक बिना किसी रुकावट के अपने काम निपटा सकेंगे। लेकिन, 26 जून से शुरू होने वाला लंबा अवकाश बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर सकता है। दरअसल, 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर कई राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे। यह अवकाश पूरे देश में लागू नहीं होगा, बल्कि चुनिंदा राज्यों और शहरों में रहेगा। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय बैंक या रिजर्व बैंक की छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। इसके बाद 27 जून को महीने का चौथा शनिवार है। भारतीय बैंकिंग नियमों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं। इसलिए इस दिन पूरे देश में बैंकिंग शाखाओं में कोई कामकाज नहीं होगा। फिर 28 जून को रविवार होने के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे। इस तरह कई क्षेत्रों में 26, 27 और 28 जून को लगातार तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं।

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने का मतलब यह नहीं है कि आपके सभी वित्तीय काम रुक जाएंगे। आज के डिजिटल दौर में अधिकांश बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आसानी से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं।

गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और इल्ख्ट जैसे यूपीआई ऐप छुट्टियों के दौरान भी सामान्य रूप से काम करेंगे। इसके अलावा ठएत्र्छ्र, फ्ळ्त्र और क्ट्ढर जैसी ऑनलाइन ट्रांसफर सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकेगा। नकदी की जरूरत पड़ने पर ग्राहक एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एटीएम सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। एक्सपर्ट का कहना है कि लंबी बैंक छुट्टियों से पहले नकदी, चेक क्लियरेंस और अन्य जरूरी लेनदेन से जुड़े काम समय रहते पूरे कर लेना बेहतर रहता है। खासतौर पर व्यापारियों, वेतनभोगी कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को अपनी वित्तीय योजना पहले से बना लेनी चाहिए। इसलिए, अगर आपका कोई महत्वपूर्ण बैंकिंग काम लंबित है, तो 25 जून से पहले उसे पूरा कर लेना समझदारी होगी, ताकि तीन दिन की छुट्टियों के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।

2 दिन में 33% चढ़ा यह स्टॉक

नई दिल्ली। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के शेयरों की कीमतों में आज 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीते दो कारोबारी दिनों में यह स्टॉक 33 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। कंपनी के शेयरों में उछाल की वजह अकडाटा सेंटर का काम मिलना है। जिसके बाद निवेशक शेयरों को खरीदने के लिए आतुर हैं। बता दें, बीएसई में कंपनी के शेयर 2490.40 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 2720.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 828.50 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 36679 करोड़ रुपये का है।

शेयरों में लगा अपर सर्किट

सोमवार को Kirloskar Oil Eagifes के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। तब कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत चढ़ा था। हायपरनेक्स ने इस कंपनी को एआई डाटा सेंटर का काम दिया है। इसी वजह से स्टॉक की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

क्या है टारगेट प्राइस

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में स्टॉक के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज हाउस ने अब शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 1955 रुपये से बढ़ाकर 2430 रुपये कर दिया गया है।

रॉकेट सा उड़ रहा 50 रुपये से कम का शेयर

नई दिल्ली। सिविल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर मंगलवार को इरए में 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 33.42 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं, पिछले एक महीने में पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में 27 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के एक संयुक्त उपक्रम (खश) को पिछले दिनों ही महाराष्ट्र में 126 करोड़ रुपये का इरिगेशन प्रोजेक्ट मिला है।

कच्चे तेल की कीमतों ने फिर दिखाई तेजी, क्या अब फिर बढ़ेंगे दाम ?

नई दिल्ली। भारत समेत पूरी दुनिया की नजर इस समय कच्चे तेल की कीमतों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 78 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी हळकक्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। हालांकि, पिछले कारोबारी सत्र में तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन निवेशक अभी भी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति कितनी तेजी से सामान्य हो पाती है। यही कारण है कि तेल बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।दरअसल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल व्यापार का बेहद अहम केंद्र है। दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस क्षेत्र में तेल आपूर्ति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। हालांकि, बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई और अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों की प्रतिबंध राहत दी, जिससे बाजार को कुछ राहत मिली। इसी वजह से सोमवार को तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली थी।

रिपोर्टः म्यूचुअल फंडों से निवेशकों का मोह भंग, मई में 40% घटा निवेश

नई दिल्ली। शेयर मार्केट में उथल-पुथल और ग्लोबल टेंशन के चलते निवेशकों का मोह म्यूचुअल फंडों से कम हो गया है। मई 2026 के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मई में इक्विटी म्यूचुअल फंडों में शुद्ध निवेश तेजी से घटा है। अटत्र्क्ष के आंकड़ों पर आधारित एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

12 महीने का सबसे निचला स्तर

रिपोर्ट के अनुसार, जियो पॉलिटिकल टेंशन, बातचीत को लेकर अनिश्चितता, सप्लाई में रुकावट की आशंकाओं और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार लगातार अस्थिर बना रहा। इस दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंडों में नेट इन्वेस्टमेंट मई 2026 में 40 प्रतिशत घटकर 22,898 करोड़ रुपये रह गया, जो अप्रैल में 38,426 करोड़ रुपये था। यह पिछले 12 महीनों का सबसे निचला स्तर है और सितंबर 2024 में बाजार सुधार शुरू होने के बाद दूसरा सबसे कम आंकड़ा है।

फ्लेक्सी कैप श्रेणी में बिक्री लगभग आधी रह गई

निवेशकों की सतर्कता दूसरी कैटेगरीज में भी दिखाई दी। रिपोर्ट बताती है कि सबसे बड़ी इक्विटी श्रेणी फ्लेक्सी कैप फंड में नेट सेल मई 2026 में लगभग आधी रह गई। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने की तुलना में फ्लेक्सी कैप फंडों की नेट सेल में 48.99 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

एसआईपी योगदान तीसरे महीने भी 30,000 करोड़ के पार

हालांकि, एकमुश्त निवेश में कमी आई, लेकिन रक्क्ष के जरिये आने वाला पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को सहारा देता रहा। रिपोर्ट के अनुसार, एसआईपी योगदान मजबूत बना हुआ है और मई 2026 में भी 30,000 करोड़ रुपये से ऊपर रहा। हालांकि, इसमें पिछले महीने की तुलना में 0.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और मार्च 2026 के शिखर से यह 3.5 प्रतिशत नीचे है। मई में एसआईपी योगदान 30,954 करोड़ रुपये रहा और लगातार तीसरे महीने यह 30,000 करोड़ रुपये के ऊपर बना रहा।

हाइब्रिड फंडों में भी सुस्ती

हाइब्रिड फंडों में भी निवेशकों की भागीदारी कमजोर रही। रिपोर्ट में कहा गया कि हाइब्रिड फंडों की नेट सेल में 48 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, बहुत सतर्क श्रेणियों जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग्स फंड में नेट सेल में मामूली सुधार देखने को मिला और यह पिछले कुछ महीनों के मुकाबले सकारात्मक हुई।

डेट आधारित योजनाओं पर भुनाने का दबाव रहा। रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में डेट और कैश सेगमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट निगेटिव रहा, क्योंकि संस्थागत ग्राहकों ने भविष्य में दरों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते विभिन्न अवधि की योजनाओं से पैसा निकाल लिया। इस दौरान डेट म्यूचुअल फंडों से 52,906 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी दर्ज की गई। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ खंड में भी कमजोरी देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि गोल्ड और अन्य ईटीएफ दोनों सेगमेंट में नेट सेल निगेटिव रही।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की दीं शुभकामनाएं

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि खेल उत्तम स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और सामूहिक सफलता की प्रेरणा देता है। ओलंपिक का आयोजन इन्हीं प्रयासों को वैश्विक स्तर पर गति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कई विभूतियों ने खेलों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी यह प्रतिबद्धता और समर्पण नमन योग्य है।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी की जयंती पर किया नमन

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां भारती के अमर सपूत, महान क्रांतिकारी श्री राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी की जयंती पर सादर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अल्पायु में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले श्रद्धेय लाहिड़ी जी का बलिदान हर भारतीय के हृदय में राष्ट्रप्रेम की अलख जगाता रहेगा।

सीएम ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक , श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी तिराहा पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र प्रथम के प्रति समर्पित प्रखर विचारधारा, देश की अखंडता के लिए उनका दृढ़ संकल्प सदैव प्रेरणा देता रहेगा। देश अनंतकाल तक डॉ.मुखर्जी का ऋणी रहेगा।

देर रात कच्चे मकान में आग, ग्रामीणों ने 3 घंटे में काबू पाया

■ अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के फुनगा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत पयारी क्रमांक-1 गांव में रविवार-सोमवार की रात कच्चे मकान में आग लग गई। ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

फुनगा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत पयारी क्रमांक-1 गांव निवासी ललुआ चौधरी के मकान में हुई। देर रात अचानक आग भड़क उठी, जिससे घर में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं नुकसान का वास्तविक आकलन अभी नहीं हो पाया है। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात व्यक्तियों ने जानबूझकर आग लगाई गई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

विकास कार्यों का जिला स्तर पर होगा प्रेजेंटेशन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी और आवासों में ईको फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को करें प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री, जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जनसामन्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, यह प्रेजेंटेशन एक तरह से विकास कार्यों के सोशल ऑडिट जैसा होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करने के लिए जिला विकास समितियां प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार समस्त सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मंत्रालय में योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, श्री मनीष रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विश्राम घाट पर ही मृत्यु पंजीयन की हो व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में सभी विभागों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों के संधारण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योजना में श्रेष्ठ कार्य तथा नवाचार करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मृत्यु पंजीयन के लिए विश्राम घाट पर ही पंजीयन की प्रक्रिया शुरू करने की व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी।

> **15 अगस्त के कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जिला स्तर पर देंगे जानकारी**

जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों पर हों आधारित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग निर्धारित किया जाए। औद्योगिक पृष्ठ भूमि, कृषि आधारित व्यवस्था, वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए विकास के सूचकांक अलग-अलग हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने के लिए भी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवाकुंर समितियों की रही सक्रिय सहभागिता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक एक लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवाकुंर समितियों ने कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदी घाट सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की। बैठक में बताया गया कि विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण के लिए जारी अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट की जा चुकी है। प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है।

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में विकसित की जाए एक हैचरी : मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश बने मछली बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एकीकृत मत्स्योघोग नीति : 2026 के कारण प्रदेश में मछली पालन सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ रहा है। प्रदेश में प्राप्त 2 लाख 91 हजार 9 सौ 38 केज के प्रस्तावों के लिए कायार्देश जारी किए जा चुके हैं।

प्रदेश में मोती उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाये, इसके लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर उनका क्रियान्वयन प्रदेश में सुनिश्चित किया जायें। प्रदेश को मछली उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना जरूरी है। अगले ढाई साल में हमें मछली बीज अन्य स्थानों से नहीं खरीदना पड़े, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभाग कार्य करे। हर जिले में एक हेचरी आवश्यक रूप से विकसित की जाये। जिलों में मछली बीज आसानी से मिलने से प्रदेश में मछली उत्पादन में और बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मछुआ कल्याण तथा मत्यस्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मंत्रालय में हुई बैठक में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह पवार, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, विभाग के सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

> **मछली पालन के लिए प्रदेश में होगा 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश**

मछुआ क्रेडिट कार्ड में मध्यप्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे मछली उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए कोल्ड चेन तथा अन्य आवश्यक इंफ्रास्टक्रर विकसित किया जाये। ब्रांडिंग और निर्यात के लिए आवश्यक नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहित किया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों के पुनर्जीवन, जलीय जीवों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करें। जलीय ईको सिस्टम को विकसित करने और जल सम्पदा पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अन्तदेर्शीय जल क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर अन्तदेर्शीय मत्स्य पालन में सिवनी जिले को वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला 25 जून को

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भोपाल में किया जाएगा कार्यशाला का आयोजन

भोपाल। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा राज्य स्तरीय कायार्शाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला 25 जून को पलाश रेसीडेन्सी भोपाल में होगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी तथा उनके सहायक शामिल होंगे।

कार्यशाला में योजना के प्रभावी संचालन, छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया, मॉनिटरिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ठरढ पर नवीन/ नवीनीकरण पंजीयन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के सीनियर कन्सलटेंट श्री राघवेन्द्र खरे उपस्थित सहभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा चयन परीक्षा में पात्र छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि सीधे हितग्राही छात्र के खाते में भेजी जाती है।

राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना राज्य के शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं नगरीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8वीं के आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए संचालित की जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए छात्र को विगत वर्ष कक्षा 7वीं में न्यूनतम ह्यसीह्न ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही, अभिभावक की सकल वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के लिए निर्धारित कोटा में मेरिट सूची के अनुसार प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश के 6 हजार 446 विद्यार्थियों का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया जाता है।

सड़क सुरक्षा में नरसिंहपुर पुलिस की अभिनव पहल बनी मिसाल

भोपाल। सड़क दुर्घटनाएं केवल आंकड़ों का विषय नहीं होतीं, बल्कि वे अनेक परिवारों के सपनों और खुशियों को प्रभावित करती हैं। इसी मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई "गोल्डन ऑवर हीरो" अभिनव पहल ने जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इस अभियान के प्रभाव से जनवरी से मई 2026 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 33 प्रतिशत, मृत्यु दर में 23 प्रतिशत तथा गंभीर घायलों की संख्या में 52 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

प्रामाणिक ज्ञान और संदर्भों के लिए पुस्तकों की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी : मंत्री

भोपाल। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि मप्र हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ मूल्य पर उपलब्ध हैं। मंत्री श्री परमार ने इन पुस्तकों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास करने तथा अकादमी की वेबसाइट पर पुस्तकों की ऑनलाइन प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। श्री परमार ने विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी बल दिया, जिससे प्राप्त सुझावों के आधार पर पुस्तकों में आवश्यक सुधार एवं संशोधन किए जा सकें। उन्होंने कहा कि परिवर्तनशीलता और निरंतर सुधार ही संस्थागत प्रगति का आधार हैं। मंत्री श्री परमार भोपाल स्थित मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सभागार में मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के 56वें स्थापना दिवस समारोह में सहभागिता कर संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री परमार ने मप्र हिंदी ग्रंथ अकादमी की 55 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अकादमी परिवार को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने देश में उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के निर्माण में अकादमी के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। मंत्री श्री परमार ने कहा कि पुस्तक लेखन एक कठिन और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है तथा लेखन का मूल भाव भारतीय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए अकादमी का कार्य एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि सतत कार्य करना अकादमी का स्वभाव बन चुका है।

गुना में दो दिन में तीन शव मिलने से सनसनी

गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र में दो दिनों के भीतर तीन शव मिलने से सनसनी फैल गई है। रविवार को एक मकान में बुजुर्ग का शव मिलने के बाद आज (सोमवार) सुबह उसी मकान के समीप बने कमरे से एक महिला और एक पुरुष के सड़े-गले शव बरामद हुए है। लगातार तीन शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत और चचार्ओं का माहौल है। पुलिस फिलहाल हत्या, संदिग्ध मौत और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बता दें कि रविवार सुबह हनुमान मंदिर के पास स्थित एक मकान से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां एक बुजुर्ग का सड़ी-गली अवस्था में शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान म्याना निवासी ओमप्रकाश शर्मा (60) के रूप में हुई थी। मृतक के भतीजे हेमंत ने बताया था कि सुबह आसपास के लोगों को चाचा के कमरे से बदबू आई। इसके बाद परिजन और पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजे पर बाहर से ताला लटक रहा था। कमरे के बाहर ताला लगा होने के कारण मामला शुरू से ही संदिग्ध नजर आया। प्रारंभिक जांच में शव तीन से चार दिन पुराना होने की आशंका जताई गई थी।

डिंडोरी में लापता मासूम का जंगल में मिला तीन टुकड़ों में शव, चार दिनों से था लापता

डिंडोरी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पांच वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। चार दिनों से लापता चल रहे मासूम का तीन टुकड़ों में शव सोमवार को गांव के पास जंगल में बरामद किया गया। शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।

जानकारी के अनुसार, करंजिया थाना क्षेत्र के तरेरा गांव निवासी इख्तियार खान 17 जून को जंगल में लकड़ी लेने गए थे। इसी दौरान उनका पांच वर्षीय बेटा इमरान सुबह घर से निकलकर पिता के पीछे-पीछे जंगल की ओर चला गया। परिवार को लगा कि बच्चा अपने पिता के साथ ही है, इसलिए शुरूआत में किसी को उसकी गैरमौजूदगी का एहसास नहीं हुआ।

जब इख्तियार खान लकड़ी लेकर वापस घर पहुंचे और बेटे के बारे में पूछा, तब परिवार को पता चला कि इमरान उनके साथ नहीं था। इसके बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में परिजनों ने करंजिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की और जंगल सहित आसपास के गांवों में सर्च अभियान शुरू किया। बच्चे की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई थी। सोमवार को गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र में बच्चे का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

घटनास्थल पर डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया है, ताकि प्रारंभिक जांच के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं।

मध्य प्रदेश में और सताएगी लू-उमस, 25 जून के बाद मानसून की दस्तक के आसार

भोपाल। मध्य प्रदेश में फिलहाल लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। प्रदेश में 26 जून तक लू, तेज गर्मी और कहीं-कहीं आंधी-बारिश का मिला-जुला असर बना रहेगा। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री-मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ गए हैं। पिछले दो दिनों से जबलपुर संभाग के कई क्षेत्रों में लू का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आज सोमवार को नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, उमरिया और डिंडौरी में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में आंधी और बारिश भी हो सकती है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट समेत कई जिलों में गर्मी का असर बना रहने का अनुमान है।

इन जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी

लू और उमस के बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी, दमोह, सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। रायसेन में 61 मिमी यानी करीब ढाई इंच वर्षा दर्ज की गई। भोपाल में दोपहर के समय तेज बारिश हुई, जबकि सतना में लगभग पौन इंच पानी गिरा। इसके अलावा जबलपुर, खजुराहो, नौगांव और सिवनी में भी बारिश दर्ज की गई।

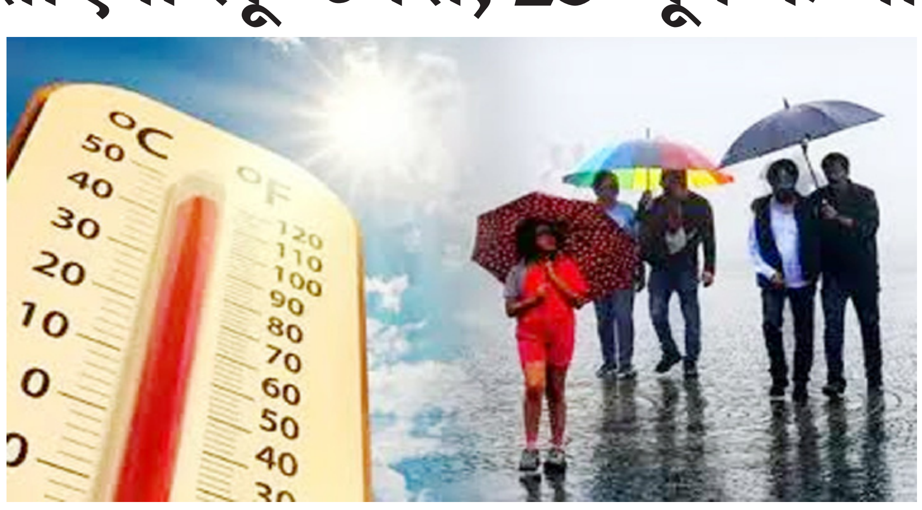

तापमान में आई गिरावट

बारिश के असर से रविवार को कई शहरों के तापमान में कमी देखी गई। भोपाल में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 37.1 डिग्री, ग्वालियर में 39.7 डिग्री, उज्जैन में 36 डिग्री और जबलपुर में 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सिवनी और शिवपुरी में 35 डिग्री, रायसेन में 36 डिग्री तथा सागर और टीकमगढ़ में 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दतिया सबसे गर्म रहा, जहां पारा 40.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

मानसून की एंट्री में और इंतजार

मध्य प्रदेश में मानसून तय समय से करीब सात दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी चार दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जबकि 25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।